सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-26 अंक-11 7 जून से 21 जून, 2011 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

भ्रम फैलाकर जनता को आन्दोलन करने से रोका नहीं जा सकता–कॉमरेड माणिक मुखर्जी

(24 अप्रैल पार्टी स्थापना दिवस पर बेंगलौर में हुई एक जनसभा में पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने वक्तव्य रखा। अंग्रेजी में दिये गये उनके भाषण का हिन्दी रूपान्तर यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। अनुवाद में त्रुटि, कमी-खामी रहने पर पूर्णतया हम जिम्मेदार होंगे। – सम्पादक स.दृ.)

कर्नाटक में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी का 64वां स्थापना दिवस उद्धरण प्रदर्शनी, पार्टी का साहित्य बिक्री अभियान आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। अन्त में 24 अप्रैल को बेंगलौर में राज्य स्तरीय एक सभा हुई। सभा में राज्य के कोने-कोने से आये कार्यकर्ता-समर्थक-हमदर्दों के अलावा भारी संख्या में आम लोगों ने भी शिरकत की। सभा के मुख्य वक्ता थे एसयूसीआई (सी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड माणिक मुखर्जी। केन्द्रीय कमेटी सदस्य, पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड के. राधाकृष्ण ने भी सभा को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड बी.आर. मंजूनाथ ने की।

सभा में कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने पार्टी गठन के संघर्ष, नेता-कार्यकर्ताओं के जीवन-संघर्ष सहित राष्ट्रीय -अन्तर्राष्ट्रीय विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हर साल पार्टी का स्थापना दिवस 24 अप्रैल के दिन हम मनाते हैं। लेकिन एसयूसीआई (सी) के कार्यकर्ता-समर्थकों के लिए यह महज एक औपचारिक रस्म अदायगी नहीं है। पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति सफल करने की शपथ इस दिन हम नये सिरे से लेते हैं। हमारी प्रिय पार्टी के नेता-शिक्षक और पथ प्रदर्शक कॉमरेड शिवदास घोष ने इस देश की माटी पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद की महान शिक्षाओं को जिस तरह विशेषीकृत किया है, उन्हें हम किस तरह जीवन में लागू करते हैं–आज आम आदमी, खासकर मजदूर वर्ग के सामने यह मिसाल पेश करने का दिन है। हम सही दिशा में चल रहे हैं कि भटक गये हैं, यह विचार करने के लिए जनता के सामने इसे पेश करना होगा। जनता है हमारी अभिभावक। वे ही हमें हमारी गलतियाँ पकड़ कर बता देंगे। हमें जनता से ही सीखना होगा और गलतियों को सुधारना होगा।

पार्टी गठन के इतिहास का वर्णन करते हुए कॉमरेड मुखर्जी ने कहा कि पार्टी की स्थापना के दौर में पार्टी के नेताओं को बहुत ही कष्टसाध्य हालात का मुकाबला करना पड़ा था। उस समय हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया(सीपीआई) नामधारी पार्टी थी। अर्न्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की मान्यता भी उसे प्राप्त थी। इसके बावजूद फिर एक और कम्युनिस्ट पार्टी गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी? कॉमरेड मुखर्जी ने कहा कि इसका जवाब बहुत ही आसान है। क्योंकि सीपीआई एक पेटी बुर्जुआ (निम्न पूंजीवादी) सोशल डेमोक्रेटिक (सामाजिक जनवादी) पार्टी थी। किसी भी देश में जनता की मुक्ति क्रान्ति के जरिए पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने से ही सम्भव है और यह क्रांति सम्पन्न कर सकती है एकमात्र सही कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में उन दिनों असली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। यह न होने की वजह से ही कॉमरेड शिवदास घोष को लेनिनीय मॉडल पर एक नई कम्युनिस्ट पार्टी गठित करनी पड़ी।

कॉमरेड शिवदास घोष अपने मुट्ठी भर सहयोद्धाओं को लेकर इस देश की सरजमीं पर एक सही मायने में कम्युनिस्ट पार्टी गठित करने के संघर्ष में जुट गये और पार्टी गठन की शर्तें पूरी होने के बाद ही उन्होंने सही कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर एसयूसीआई की स्थापना की। सीपीआई ने उन दिनों हमारे देश के आजादी आन्दोलन में विश्वासघातक की भूमिका निभायी थी और अंग्रेजों की प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में मदद कर आजादी आन्दोलन का विरोध किया था। सीपीआई की इस भूमिका के कारण देश के लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा 'कम्युनिज्म' का विरोधी हो गया था। इसीलिए उस समय हमारी पार्टी का नाम 'कम्युनिस्ट पार्टी' नहीं रखा जा सका।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता-कार्यकर्ताओं ने तहेदिल से कम्युनिस्ट बनना चाहा था। इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग भी किया था। कॅरियर छोड़ दिया था, मजदूर-किसानों में जाकर उन्हें संगठित कर आन्दोलन गठित किये थे, यहाँ तक कि जान निसार करने में भी उन्होंने पीछे कदम नहीं हटाये थे। लेकिन इतना कुछ करने पर भी वे कम्युनिस्ट नहीं बन पाये थे। कॉमरेड शिवदास घोष ने इसके कारण का विश्लेषण और व्याख्या करते हुए दिखाया था कि कम्युनिस्ट बनना चाहना अवश्य ही एक महत्त्वपूर्ण बात है। लेकिन महान लेनिन द्वारा निर्देशित विज्ञान सम्मत तरीके का अनुसरण करके ही एकमात्र कम्युनिस्ट बनना सम्भव है। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी में इस पद्धति की ही कमी थी। नतीजतन, ये सब नेता-कार्यकर्ता जिस तरह एक सही कम्युनिस्ट पार्टी गठित करने में नाकाम रहे, उसी तरह खुद भी सही कम्युनिस्ट नहीं बन पाये।

कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने कहा कि कॉमरेड शिवदास घोष दिखा गये हैं कि मार्क्सवाद है कर्म का मार्गदर्शक। लेकिन केवलमात्र मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग की किताबें पढ़कर ही कोई मार्क्सवादी नहीं बन सकता है। लेनिन ने दिखाया है कि जीवन में लागू किये बिना मार्क्सवाद सीखा नहीं जा सकता। लेनिन की इस शिक्षा के आधार पर कॉमरेड

(शेष पृष्ठ 4 पर)

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए कृषि व्यापार का द्वार खोलने का एसयूसीआई(सी) द्वारा विरोध

बड़े-बड़े कार्पोरेटों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए कृषि क्षेत्र व्यापार का दरवाजा खोल देने का जोरदार विरोध करते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 30 मई को जारी किये एक प्रैस बयान में कहा कि कृषि जनित मालों के दाम घटाने के बहाने बड़े-बड़े कार्पोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए कृषि क्षेत्र का व्यापार का दरवाजा खोल देने के कांग्रेस-नीत केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावित कदम का हम कड़ा विरोध करते हैं। सरकार जब धड़ले से जमाखोरी, कालाबाजारी, सट्टेबाजी चलने देकर खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान पर पहुँचाती जा रही है और खाद्यान्नों समेत दूसरी सभी आवश्यक चीजों का सम्पूर्ण राष्ट्रीय वाणिज्य चालू करने की जनता की माँग न मान कर कीमतो पर काबू पाने से इनकार कर रही है, तब यह नया प्रस्ताव मुनाफाखोर कार्पोरेट घरानों और बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कृषि क्षेत्र में पैर जमाने देकर चीजों के दाम तय करने का ऐसा मौका देगा जो जनता की जेब से आखिरी पैसा तक निचोड़ कर उनके मुनाफे का अम्बार लगा देगा। इसके अलावा, यह नया प्रस्ताव लाखों-लाख छोटे-छोटे दुकानदारों की तबाही में तेजी ला देगा, अनगिनत कर्मचारियों की भी नौकरियाँ छिन जाएंगी। इस प्रक्रिया में अनगिनत गरीब छोटे और मझौले किसान जमीन का मालिकाना हक खो बैठेंगे जो निश्चित रूप से उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर कर देगा। नई उदारनीति के टोटकों से मेल खाती योजना देशी एकाधिकारी पूंजीपतियों के स्वार्थ में तैयार की गई है जिससे देश के कृषि जनित पैदावारों के बाजार को विदेशी पूंजीपतियों के सामने खोल देने के बदले में ये पूंजीपति विदेश के बाजार में और भी ज्यादा हिस्सा पा सकें।

यह विनाशकारी कदम उठाने से बाज आने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए हर तबके के मेहनतकश लोगों और सही मायने में वाम-जनवादी ताकतों को जोरदार आन्दोलन गठित करने के लिए आगे आने का हम आह्वान करते हैं।

भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन से उभरे कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

अब एक साल से ज्यादा अर्से से भारत घोटालों से शर्मसार है–2जी स्पेक्ट्रम अनियमितताएं, आईपीएल की लूट, राष्ट्रमण्डल खेलों में मची लूट-खसोट, आदर्श हाउसिंग सोसायटी सकैण्डल, केन्द्रीय सर्तकता आयुक्त (सीवीसी) की पक्षपातपूर्ण नियुक्ति संसद में नोट के बदले वोट, हसन अली द्वारा दो नम्बर के धन को एक नम्बर में बदलना, विदेशी बैंक खातों में भारी मात्रा में पड़ा काला धन और यह काली सूची बढ़ती ही जा रही हैं। लोगों का कड़वा तजुर्बा है कि उनके जायज से जायज काम भी रिश्वत के बिना नहीं होते हैं। लोग इससे तंग आ चुके हैं। चाहे किसी को मृत्यु प्रमाणपत्र या बीपीएल कार्ड लेना हो, चाहे किसी को पेयजल कनैक्शन या स्वास्थ्य केन्द्र में मामूली इलाज की जरूरत हो वह उसके दरवाजे सदा बंद पाता है या देश में कायम तमाम कायदे-कानून ताक पर रखकर पिछले दरवाजे से काम निकालने के नजरिये का ही बोलबाला है। भ्रष्टाचार की जड़ें जीवन के हर क्षेत्र में फैली हुई हैं और सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र को दमघोंटु नागपाश में लिया हुआ है। इन घोटालों और सर्वव्यापक भ्रष्टाचार के बारे में सबसे ज्यादा चिन्ता की बात यह है कि राजनैतिक प्रतिष्ठानों, शासक पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की ओर से जवाबदेही की कमी है जो पहले से ही रोकथाम की कोई कार्रवाई करने में अपनी नाकामी की वजह के तौर पर ''जायजा लेने में गलती'' या ''गठबंधन राजनीति की मजबूरी'' को बेशर्मो से दिखा रहे हैं। सरकार सकैण्डल युक्त भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी हुई है। यह न केवल अपराधों को बढ़ावा देती और अपराधियों को बचाती पायी गई है बल्कि लोगों से तत्परता से सफेद झूठ बोलती पायी गई है। देश के वित्त मंत्री को संसद में यह घोषणा करते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ कि देश से हजारों करोड़ रुपये चोरी से बटोर कर विदेशी बैंकों में सुरक्षित जमा रखने वालों के नाम कानूनी वजह से वे उजागर नहीं कर सकते। सरकार और संदिग्ध घोटालेबाज अपने बचाव में मुलम्मा लपटने के लिए एक ही रट लगाये हुए हैं कि ''कानून अपना काम करेगा।'' हालाँकि इतिहास के साथ चलें, तो लोग यह विश्वास करने से इनकार कर देते हैं कि गलत काम करने वालों को कभी उनके किये की सजा मिलेगी। उल्टे, वे

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन...

(पृष्ठ 1 का शेष)

अनुभव से यह जानते हैं कि अपराधी, काला धन रखने वाले और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ-अफसरशाह-बड़े-बड़े कारपोरेट घराने मौज लेते रहेंगे, सरकारी शासन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे रहेंगे और देश के नीति निर्माता बने रहेंगे। भले ही, जनता को दिखाने के लिए उनमें कुछ कभी-कभी पकड़े भी जायें, यह उनके लिए कोई गंभीर जोखिम की बात नहीं है क्योंकि सत्ता के गलियारों में घोंसला बनाये बैठे अपने ''सम्पर्क सूत्रों'', ''आकाओं'' और ''गॉड फादरों'' के चलते वे जानते हैं कि सजा का जोखिम अगर कुछ है भी तो बहुत ही नगण्य है। जबकि एक गरीब आदमी, अगर किसी छोटे से भी मामले में कसूरवार पाया जाता है, तो निरअपवाद रूप से उसे सजा मिलती है। लेकिन यह देखने को मिलता है कि अमीर और समाज का ऊपरी हिस्सा बड़े पैमाने पर कानून का उल्लंघन करने, कानून तोड़ने, कानून का दुरुपयोग करने और कानून मानने से खुला इनकार करने पर भी बच निकलते हैं और उनका बाल भी बांका नहीं होता है। बेईमानों के लिए सरकार में एक जोखिम रहित माहौल तैयार कर दिया गया है। इसलिए बुर्जुआ संसदीय राजनीति में अब ऐसे काइयाँ मुजरिमों, धन की हेराफेरी करने वालों, अपना घर भरने वालों, सार्वजनिक कोष का गबन करने वालों की भरमार हो गयी है और मंत्रियों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेलगाम भ्रष्टाचार व्याप्त है।

चौतरफा फैले भ्रष्टाचार की जड़

साफ जाहिर है कि समझदार आदमी इन सब बातों को लेकर गहरे चिन्तित हैं और हैरान हैं कि ऐसी गहरी जड़ जमाये बैठी संस्थानीकृत बुराई से कोई छुटकारा भी मिल पायेगा या नहीं। इन सब लोगों के सामने एक बात पहले ही साफ है। यह गहराई से समझ लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार कुछ एक सुविधाभोगी ठग-बेईमानों, सत्ता की कुर्सी पर कब्जा जमाये बैठे गलत काम करने वालों या अकूत धनबल वालों की काली करतूत ही नहीं है। लिहाजा यह विचार कि अगर उपयुक्तत कानून का अधिकार प्राप्त करके इन तत्वों से निपटा जाये, तो भ्रष्टाचार की समस्या हल की जा सकती है, मूर्खों के स्वर्ग में वास करने जैसा है। हमारे देश जैसे एक पूंजीवादी ढाँचे में यह अपेक्षा करना कि महज कुछ कानूनी प्रावधानों को बदलकर या नये कानून बनाकर चौतरफा फैले भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सकता है, यह खयाली पुलाव है। ऐसा भ्रम पालना पूरी तरह नाकामयाबी, विफलता की स्थिति में ले जाएगा और भ्रष्टाचार की सुरसा का बाल भी बांका नहीं होगा। भ्रष्टाचार की इस निरंतर बढ़ोतरी से समाज को निजात दिलाने के लिए कार्रवाई का सही रास्ता पाने के लिए किसी को भी समस्या का कारण ढूँढ़ना होगा। प्रकृति में कोई भी परिघटना ऐसी नहीं है जिसका निश्चित कारण न हो, एक निश्चित वस्तुगत कारण न हो। हर घटना-परिघटना या पथभ्रष्टता के पीछे कार्य-कारण का नियम काम करता है। जैसा कि पूर्ववर्ती कई लेखों में हमने व्याख्या करके बताया है कि चाहे धन के रूप में हों या सत्ता, प्रतिष्ठा और अनुचित लाभ आदि गैर वित्तीय रूपों में हों तुच्छ संकीर्ण व्यक्तिगत फायदे उठाने के लिए कानून-कायदों, उसूलों और दस्तूरों को ताक पर रख देना, जान बूझकर कदाचार में संलिप्त होना भ्रष्टाचार है। लोभ-लालच में पड़कर या छिपे इरादे से व्यक्तिगत भ्रष्टाचार कर बैठने की छुट-पुट घटनाएँ एक सभ्य समाज में भी घटित हो सकती हैं लेकिन, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उनको सजा न मिले। लेकिन भ्रष्टाचार को तब तक संस्थानीकृत नहीं किया जा सकता जैसाकि आज देखा जा रहा है, जब तक कि मौजूदा व्यवस्था ही सड़ी-गली न हो जाए, वह जीवन के हर क्षेत्र में पतन में सहायक न हो जाए। एक ध्यानपूर्वक तर्कसंगत विश्लेषण दिखा देगा कि जिस पूंजीवादी व्यवस्था में हम रह रहे हैं वही तमाम पथभ्रष्टता और भ्रष्टाचार की जड़ है।

इस संबंध में यह बेहद गौरतलब है कि जब तक सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था, एक विचारधारा या नैतिकता की एक धारणा सामाजिक प्रगति की परिपूरक होती है और सभ्यता की अग्रगति के लिए लड़ती है, तब तक यह उन्नत संस्कृति और नीति-नैतिकता प्रदान करती है। लेकिन जब, सामाजिक विकास की अटल प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए वही व्यवस्था या विचारधारा प्रतिक्रियावादी बन जाती है, तो सामाजिक प्रगति को बाधित कर देती है और सभ्यता की अग्रगति को रोक देती है, यह नीति नैतिकता में झट से गिरावट ला देती है और भ्रष्टाचार को पनपाती है।

उदीयमान पूंजीवाद के शुरूआती दौर में संसदीय राजनीति के पैरोकार बुर्जुआ लोकतंत्र की भावना से मार्ग दर्शित थे जिसने इसके आगमन काल में पुरानी गई-गुजरी प्रतिक्रियावादी सामन्ती व्यवस्था, राजे- रजवाड़ेशाही को हटा कर उसकी जगह नये सारतत्व वाली नई लोकतांत्रिक व्यवस्था लानी चाही थी और इसके आने से कुछ प्रगतिशील मूल्यबोध, रीति-नीति, नीति-नैतिकता आई थी जिन्होंने पूरे समाज में हलचल मचा दी थी और लोगों में नई जागरूकता आई थी। लेकिन आज पूंजीवाद मृत्यु शय्या पर पड़ा तड़फ रहा है, अपने मरणासन्न जीवन की घड़ियों को बढ़ाने की बदहवास कोशिश कर रहा है जो सामाजिक प्रगति को बाधित कर रहा है। क्योंकि मरणासन्न पूंजीवाद प्रतिक्रियावादी हो गया है, इसलिए यह आज कोई उन्नततर विचारधारा को नहीं पाल-पोस रहा है। पतनशील मरणासन्न पूंजीवाद जो अपने पतनोन्मुख अस्तित्व की घड़ियां लम्बी करने के अपने प्रयास में सभी कायदे-कानूनों को बाकायदा तोड़ता जा रहा है तमाम रीति-नीतियों और दस्तूरों की धज्जियां उड़ाता जा रहा है जिनका अपने आगमन काल में इसने खुद ही प्रचार किया था और जिन महान आदर्शों का इसने कभी प्रचार किया था आज यह अपने उन मौलिक उपदेशों को एकदम पैरों तले रौंदता जा रहा है, यह जिन लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यबोधों का कभी चैम्पियन होता था, आज उनका अदण्डित उल्लंघन करता जा रहा है, उसे डर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, नीति-नैतिकताओं में से जरा सी अगर बची रह गई और पैदा की गई तो इसके दमनात्मक, निरंकुश शासन के खिलाफ विरोध में उठ खड़े होने का जज्बा पैदा होने में मदद मिलेगी। इस प्रकार उसका घिसा-पिटा, चरमराता अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जितना ज्यादा पूंजीवाद इस व्यवस्था की स्थानिक महामारी मंदी के संकट में फंसता जा रहा है, सभी आचार-संहिताओं और मूल्यबोधों के धूल में मिलते जाने की प्रक्रिया उतनी ही तेज होती जा रही है। पूंजीवाद के इतने नग्न रूप से प्रतिक्रियावादी होते जाने से, लोभ-लालच, सत्ता व धन की भूख और हर कीमत पर अपना घर भरने का ऊपर से लेकर नीचे तक बोल-बाला हो गया है। पूंजीवाद आज हरेक को धन- दौलत के पीछे पागल होने की दिशा में धकेलता जा रहा है। उसके चक्कर में पड़ जाने से रुपये बनाना जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। यह ऊपर की कमाई करने की अंधी दौड़ इस विचार को उभार रही है कि जीवन का आदर्श वाक्य है येन केन प्रकारेण धन हड़पना। बाकी सब चीजें धन के पीछे हाथ धोकर पड़ने के मुकाबले गौण हैं। ऐसे विचार यूं ही हवा से नहीं आते बल्कि सड़े-गले पूंजीवाद की इसी सामाजिक- आर्थिक व्यवस्था से पैदा होते हैं। पूंजीवाद में अवश्यम्भावी तौर पर लोगों की तेजी से गिरती खरीद शक्ति की वजह से हल न हो सकने वाले बाजार संकट में फंस जाने से शासक पूंजीपति वर्ग आज उत्पादक पूंजीनिवेश में अधिकतम मुनाफा कमाने की कोई गुंजाइश नहीं पाता है। इसलिए, यह सट्टेबाजी, सूदखोरी करने और धन बनाने के ऐसे ही अन्य तौर तरीकों में पूंजी लगा रहा है जो धोखाधड़ी, छल-कपट, उल्लू बनाने और ठगने से प्रारम्भ हुए हैं। रुपया बनाने का कोई भी सट्टेबाजी का खेल जीतना पहले से यह मान कर चलता है कि वह दूसरों को झांसा देने में कितना माहिर है। शेयर बाजार का कार्य संचालन जो पूंजीवाद में सबसे बड़ी सट्टेबाजी की गतिविधि है वास्तव में दाव लगाने और जुए पर आधारित है। समय गुजरने के साथ-साथ व्युत्पन्न व्यापार (Derivative trading), ऋणों का प्रतिभूतीकरण आदि जुआखोरी के नये-नये तरीके खोज निकाले जा रहे हैं जिसे पूंजी बाजार में कहा जाता है इस व्यापक पैमाने पर फैली सट्टेबाजी को 'गहराई एवं विस्तार देना' इसी तरह, पूंजी को अब बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के जरिए और सूदखोरी की गतिविधि यों में ज्यादा से ज्यादा लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि शेयर बाजारों में बहुत बड़े पैमाने की सट्टेबाजी के लिए धन मुहैया कराने के लिए भी लगाया जा रहा है। दरअसल, मरणासन्न पूंजीवाद में आर्थिक गतिविधि एक जुआरियों के अड्डे में तब्दील हो चुकी है जहाँ सभी कार्यकलाप धूर्त हस्त कौशल के जरिए दूसरों को ठगकर अपनी खुद की तिजोरियाँ भरने के एकमात्र उद्देश्य के ही इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। असल में चौबीसों घंटे, एक अंधी होड़ चलती रहती है कि धन पाने और फायदा उठाने के लिए कौन किसको ठग सकता है या धोखाधड़ी कर सकता है। बड़े-बड़े कार्पोरेट और एकाधिकार पूंजीपति घराने भी इस जुआखोरी के धंधे में सीधे संलिप्त हैं। वे धन के अम्बार लगाने के लिए धड़ल्ले से नियम-कानूनों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कार्य-प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और अनापशनाप गैर कानूनी हथकण्डों व गतिविधियों में संलिप्त हैं। मामला ऐसे नाजुक मोड़ पर आ पहुँचा है कि घूसखोरी, कमिशनखोरी, किक बैक, रिश्वतखोरी को 'सुविधा शुल्क', 'आधार भूत संरचना राशि' आदि नई-नई रची शब्दावली के तहत वित्तीय विवरणों, हिसाब खातों में संस्थानीकृत किया जा रहा है।

पूंजीवाद की इस अवश्यम्भावी परिणति को पहले ही भांपकर मार्क्स ने 150 साल पहले कहा था कि पूंजीवाद में, धन सर्वशक्तिमान बन गया है और सभी रिश्ते सारे प्राकृतिक और भावात्मक फर्कों को मिटाकर और उनकी जगह धन की कमाई करने की खास भौतिक चीज के अमूर्तीकरण में मन में आसन जमाकर रुपये-पैसे के रिश्तों में तब्दील होते जा रहे हैं और एक खास चेतना को जन्म दे रहे हैं जो इस चीज के दाससुलभ अधीन है। सर्वव्याप्त भ्रष्टाचार हर जगह पनप रहा है और इसलिए अमेरिका से लेकर किसी छोटे से छोटे देश तक, कुछ फर्कों के बावजूद, समूची पूंजीवादी-साम्राज्यवादी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत में, जैसेकि एसयूसीआई (सी) के संस्थापक महासचिव और इस युग के एक अग्रणी मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा शानदार ढंग से विश्लेषण किया गया था कि ''पूंजीवाद का विकास और राष्ट्रीय आजादी आन्दोलन की वृद्धि ऐसे समय हुई जब विश्व पूंजीवाद अपने सारा प्रगतिशील चरित्र खो चुका था और घोर प्रतिक्रियावादी व मरणासन्न हो चुका था। भले ही भारतीय राष्ट्रीय पूंजीवाद साम्राज्यवाद-विरोधी था, पर निःसंदेह यह मरणासन्न विश्वपूंजीवाद का एक अभिन्न अंग था। यही वजह है कि पूंजीवादी क्रांति के दौर में देखा गया इसका क्रांतिकारी चरित्र विश्व साम्राज्यवाद और मरणासन्न पूंजीवाद के दौर में उसमें बचा नहीं था। इसलिए हालांकि भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी पूंजीवाद का अभिन्न अंग होते हुए साम्राज्यवाद विरोधी आजादी की लड़ाई में नेतृत्व दिया लेकिन इसमें क्रांतिकारी चरित्र नहीं था—उल्टे यह मुख्यतः साम्राज्यवाद के खिलाफ सुधारवादी विरोध पक्ष बनकर रह गया था।'' इस निश्चित सामाजिक-राजनीतिक कारण से, भारतीय राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बुर्जुआ मानवतावाद का वैचारिक पतन पहले ही शुरू हो गया था उससे मुक्त रहना ऐतिहासिक रूप से असम्भव था। उसके नतीजे के तौर पर, देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला पश्चिमी पूंजीवादी देशों से भी ज्यादा है और यह उनसे भी ज्यादा व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है। इसलिए साफ जाहिर है कि कमरतोड़ कंगाली और बदहाली की बढ़ती समस्या से पहले ही त्रस्त लोगों को लील रहे भ्रष्टाचार की यह समस्या इस पतनशील मरणासन्न पूंजीवाद द्वारा ही पैदा की हुई है और इसलिए मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में यह समस्या दूर नहीं हो सकती है। जाहिर है कि भ्रष्टाचार को दूर करने का सवाल पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के सवाल के साथ ओतप्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक है कि जो लोग पूंजीवाद को गिराने के संघर्ष में जुटे हुए हैं उनके सोच-विचार, मूल्यबोधों और नीति-नैतिकता में ही भ्रष्टाचार और तमाम दूसरे दुराचारों की काट निहित है। भ्रष्टाचार के इस हिम स्खलन के खिलाफ जेहाद छेड़ने का तौर-तरीका पूंजीवाद को अन्तिम रूप से उखाड़ फेंकने की तैयारी की प्रक्रिया में सच्चे क्रांतिकारियों द्वारा विकसित आन्दोलनों में ही निहित है। जब तक राज्य क्रांति के द्वारा मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था को बदल नहीं दिया जाता, भ्रष्टाचार और अन्य पापों से एकमात्र बचाव है पूंजीवाद-विरोधी क्रांतिकारी आन्दोलन के परिपूरक उन्नततर नीति-नैतिकता और संस्कृति की नींव पर लोगों के संगठित दीर्घकालिक जनवादी आन्दोलनों की उठती लहरें जनआन्दोलन का यह परिवेश। आन्दोलन की भावना से पोषित विचारों का यह क्षेत्र ही है जो भ्रष्टाचार, घोटालों और सकेण्डलों के होने पर कारगर रोक लगाएगा, जनजीवन के ज्वलन्त मुद्दों

(शेष पृष्ठ 6 पर)

भारत में 10 करोड़ लोग जमीन से बेदखली के रूबरू

भारत में 17 राज्यों के 40 जिलों में लगभग 4 लाख एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण का जोड़तोड़ चल रहा है। इसके फल स्वरूप किसान-खेतमजदूरों सहित लगभग 10 करोड़ आम लोग जमीन से बेदखल होने के कगार पर हैं। यह जमीन अधि कतर उपजाऊ और बहुफसली है।

विश्व पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में आई मन्दी की मार से भले ही वक्ती तौर पर सही, बचने के लिए पूंजीपति आवासीय ईमारतें, टाऊनशिप बनाने के धंधे की तरफ रुख कर रहे हैं। इन्हें औने-पौने दामों पर सस्ती जमीन दिलाने के लिए सरकार जनहित के नाम पर ब्रिटिश शासनकाल के जमीन अधिग्रहण कानूनों का इस्तेमाल कर निहायत कम कीमत पर किसानों की जमीन जबरन छीन रही हैं। केवल आवासीय इमारतों के बिल्डरों को ही नहीं बल्कि पूंजीपतियों को बेहद मुनाफा दायक स्वर्ग राज्य 'सेज' बनाने के लिए भी हजारों हजार एकड़ जमीन दी जा रही है। कहीं हाइवे परियोजना के नाम पर किसानों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है जबकि हकीकत यह है कि महामंदी में फंस चुके मरणासन्न पूंजीवाद में अब औद्योगिकीकरण व विकास की कोई गुंजाइश नहीं रही है। सिर्फ देशी कम्पनियों को ही नहीं, बल्कि भूमण्डलीकरण के खुले द्वार की नीति के तहत बाहर से आने वाले विदेशी एकाधिकारी पूंजीपतियों को भी जमीन दी जा रही है। सरकार खुद भी किसानों से कौड़ियों के भाव जमीन खरीद कर कई गुना मंहगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रही है और पूंजीपतियों के लिए दलाली कर रही है। इस समग्र मुनाफाखोरी की बलि चढ़ रहे हैं भारत के 10 करोड़ आम आदमी। जो पार्टियाँ चुनाव के समय जनहितैषी के रूप में खुद को पेश करती हैं, काम करने वाले और लोगों के अपने आदमी के तौर पर जिन नेताओं को पेश करती हैं वे ही तो कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, बीजेडी सरकारें लोगों को उजाड़ने जमीन से बेदखल और बेघर करने वाले इस नरमेध यज्ञ मे आहूति देने वाली सरकारें हैं। यहाँ तक कि तथाकथित वामपंथी सीपीआई (एम) सीपीआई भी जहाँ सरकार में थी, किसानों की जमीनें छीनने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में सिंगुर में टाटा की नैनो कार फैक्ट्री के लिए 1000 एकड़ और नंदीग्राम में इण्डोनेशिया के सलेम समूह के लिए 10 हजार एकड़ जमीन जबरन अधिग्रहण करने के लिए ऐडी-चोटी का जोर लगाया, नंदीग्राम में किसानों पर पुलिस और पार्टी के क्रिमिनलों के द्वारा बर्बर हमला किया। किसानों को मौत के घाट उतारा व महिलाओं की इज्जत लूटी। लेकिन किसानों के ऐतिहासिक आन्दोलन के कारण वह सफल नहीं हो सकी। हरियाणा में कांग्रेस ने रिलायन्स के 25,000 एकड़ जमीन जिसमें गुड़गांव व झज्जर जिले के लगभग 40 गाँव आते है और अन्य परियोजनाओं के लिए 2005-2010 के बीच करीब 60 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहण जा रही है। गुजरात में बीजेपी सरकार द्वारा साणंद में टाटा की नैनो परियोजना के लिए 7 गाँवों की करीब 8 हजार एकड़ जमीन छीनने पर बवाल हुआ। आंध्रप्रदेश में करीब 20 लाख एकड़ जमीन को गैर कृषि कार्यों में बदल दिया गया। मध्य प्रदेश में करीब 4.40 लाख हैक्टेयर जमीन पिछले 5 वर्षों के दौरान अधिग्रहीत की जा चुकी है। उड़ीसा के जगदीश पुर में दक्षिण कोरिया की कम्पनी पोस्को के लिए जमीन अधिग्रहण पर विवाद है और कलिंगनगर में टाटा स्टील के लिए आदिवासियों पर गोलियाँ चलाई गयी। उ.प्र. में भट्टा पारसौल में जबरन जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों पर मायावती सरकार ने लाठी-गोली चलवाई जिसमें 3 किसान मारे गये। फिलहाल किस राज्य में किस जिले में जमीन से बेदखली होने जा रही उसकी सूची में ये आँकड़े और जुड़ गये हैं:

राज्य	जिले	जमीन (एकड़ में)
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, चंदौली, गौतमबुद्धनगर	1,76,336
महाराष्ट्र	नागरपुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे	45,600
छत्तीसगढ़	बस्तर, जांजगीर-चंपा	42,063
उड़ीसा	जगतसिंह पुर, जाजपुर, काला हांडी, गंजाम	41,800
गुजरात	भावनगर, कच्छ	6,529
हिमालय प्रदेश	कुल्लू, किन्नौर, श्रीमौर, चंबा	2,817
बिहार	औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर	1,744
आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी, महबूबनगर, श्रीकाकुलम, नेल्लोर, विशाखापत्तनम	21,739
हरियाणा	फतेहाबाद	1,500
पंजाब	मोहाली	770
तमिलनाडु	मदुरई, तिरुवल्लुर, तूतीकोरिन	5,000
चंडीगढ़		167
मेघालय	ईस्ट खासी	111
केरल	कोच्चि	100
कर्नाटक	डी कन्नडा	1800

(तथ्यसूत्र : टाइम्स ऑफ इण्डिया, 23-5-2011, दैनिक जागरण, 22 मई, 2011)

बस्ती बचाओ संघर्ष समिति द्वारा मेधा पाटकर का समर्थन

सरकार द्वारा गरीबों के घरों को तोड़कर बिल्डरों के हवाले किए जाने के खिलाफ 26 मई को बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में मुम्बई में सुप्रसिद्ध समाजसेविका मेधा पाटकर द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के समर्थन में, एलबर्ट एक्का चौक पर एकदिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किए गया। ज्ञात हो कि बस्ती बचाओ संघर्ष समिति अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ लगातार आंदोलनरत है।

कार्यक्रम में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक श्री सिद्धेश्वर सिंह ने कहा कि-'जीने का अधिकार' व 'रहने का अधिकार' मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। यह सरकार का दायित्व बनता है कि वह इस ओर नजर रखे कि ये सारे अधिकार लोगों को हासिल हो रहा है या नहीं। लेकिन हमारे देश की एक बहुत बडी आबादी घरों के अभाव में खानाबदोशों की तरह जिंदगी जिने में विवष्ठा है। सभी प्रकार के मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। एच.ई.सी. के 22 गाँव बस्तियों को कुछ उद्योगपतियों के व्यवसायिक हित में उजाड़ने का फैसला पूर्ण रूप से अमानवीय है। मुम्बई में गरीबों के जमीन को बिल्डरों के हवाले किए जाने के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठी प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को हमारा पूर्ण समर्थन है और देश में जहां कहीं भी गरीबों के घरों को उजाड़ने के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, समिति उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है।

समिति की संस्थापिका केया डे ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह तानाशाही के सिवाय और कुछ भी नहीं है। एच.ई.सी. की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के 22 गांव बस्तियों में जो लोग बसे हुए हैं उनके पूर्वजों को घरों के अभाव में प्रबंधन द्वारा ही जमीन मुहैया कर बसाया गया था। इनमें एक तो वे थे जो एच.ई.सी. के मजदूर के रूप में कार्यरत थे। दूसरे वे लोग थे जिन्होंने इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और तीसरे वे लोग थे जिन्होंने इन लोगों के लिए सेवामूलक कार्य किया मसलन ठेला चालक, रिक्शा चालक इत्यादि। आज करीब 50-60 वर्षों के बाद इन्हें अतिक्रमणकारी कहकर उजाड़ने की साजिश चल रही है। सरकार दलील दे रही है कि यह न्यायालय का आदेश है, इसलिए वह विवश है। न्यायालय का आदेश यह नहीं है कि गरीबों की बस्तियों को ही उजाड़ा जाना चाहिए। आदेश यह नहीं है कि अगले ही दिन गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाए। अगर यह एक जनकल्याणकारी सरकार होती तो अब तक गरीबों के पक्ष में अध्यादेश ला सकती थी। परंतु सरकार कुछ उद्योगपतियों की गुलामी के सिवाय और कुछ भी नहीं कर रही है। एच.ई.सी. क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए। समिति इसके लिए आंदोलन करती आई है और करती रहेगी। मेधाजी को भी हमारा पूर्ण समर्थन है।

संयोजक मिंटु पासवान ने कहा कि हमें अवैध कहा जा रहा है। अगर हमारा वोट अवैध है, तो वे नेता मंत्री भी अवैध हैं जो हमारे वोटों के द्वारा आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अगर हमारा राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, वोटर्स कार्ड वैध है तो हम अवैध कैसे हुए? हमारे लिए पुनर्वास की बात करना बेमानी है। हमें जमीन का मालिकाना हक देना ही होगा। सरकार न्यायालय के आदेश का हवाला दे रही है। लेकिन गौरतलब बात है कि यह न्यायालय का ही आदेश है कि फीस वृद्धि पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन हर साल स्कूल कॉलजों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ायी जा रही है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि गोदामों में जो अनाज पड़ा हुआ है उसका सही वितरण होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे। लेकिन हर साल लाखों लोग भूख और कुपोषण के शिकार हो रहे है। वहीं गोदामों में अनाज पड़े-पड़े सड़ जाता है। इस ओर सरकार की नजर नहीं जाती। कार्यक्रम में दावलीन खलखो, राम नरेश राम, रेशमी टोप्पो, शिवम, विक्टोरिया टोप्पो, आशा तिर्की, सोमनाथ नायक, जितेन्द्र राम, किशन राम व अन्य लोगों ने भी अपनी बात रखी।

22 मई को रांची में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जन सुनवाई

भ्रम फैलाकर जनता...

(पृष्ठ 1 का शेष)

शिवदास घोष ने पार्टी के अन्दर सामूहिक जीवनयापन का एक समाजवादी संघर्ष शुरू किया था। सामूहिक जीवन यापन की मूल बात है राजनीतिक, आर्थिक, प्रेम, यौनता, व्यक्तिगत जीवन संबंधी पहलू सहित जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त करके पार्टी के नेता-कार्यकर्ताओं में समचिन्तन, समदृष्टिकोण और समउद्देश्यमुखीता निर्मित कर डालना। क्योंकि वर्ग विभाजित समाज में जीवन के हर क्षेत्र में ही कोई न कोई वर्ग दृष्टिकोण काम करता है। समचिन्तन पद्धति अपनाने का मतलब है कौन सा चिन्तन सर्वहारा वर्ग का चिन्तन है और कौन सा नहीं–यह पहचान लेना और सही वर्ग चिन्तन अपनाने के संघर्ष में लग जाना।

उन्होंने कहा कि सर्वहारा वर्ग दृष्टिकोण अपनाये बिना जिस तरह कम्युनिस्ट नहीं बना जा सकता, उसी तरह सर्वहारा क्रांति भी सफल नहीं की जा सकती। इसीलिए कम्युनिस्ट होने की आवश्यक शर्त है बुर्जुआ और पेटी बुर्जुआ आदत-आचरणों और ध्यान-धारणाओं से मुक्त होना, सही सर्वहारा वर्ग दृष्टिकोण सम्मत ध्यान-धारणाएं निर्मित करने के लिए पार्टी के अन्दरूनी सामूहिक जीवन में व्यापक चर्चा-बहस और तर्क-वितर्क करने की जरूरत है। इस तरह कॉमरेड शिवदास घोष ने जीवन के तमाम पहलुओं में व्याप्त एक समाजवादी संघर्ष शुरू किया। वे इसी संघर्ष के रास्ते कॉमरेड शिवदास घोष सामूहिक नेतृत्व के विशेषीकृत मूर्त रूप और पार्टी के नेता, शिक्षक, पथ प्रदर्शक तथा महान मार्क्सवादी दार्शनिक के तौर पर उभर कर आये थे।

उन्होंने आगे कहा, यह समझाने के लिए कि एसयूसीआई(सी) ही एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी है, हमें काफी संघर्ष करना पड़ा है। आज यह बात कई लोग जानते हैं। सीपीआई लगातार टूटते-टूटते अब सीपीआई(एम), विभिन्न नक्सलपंथी गुटों और तथाकथित माओवादी दलों में विभाजित हो चुकी है। इन दलों, गुटों, पार्टियों के कामकाज, आचार-आचरण देखकर लोग आज इन्हें कम्युनिस्ट नहीं मानते हैं लेकिन पहलेपहल लोगों को यह बात समझाना बहुत ही मुश्किल था।

संशोधनवाद पर अमल करने की वजह से और साम्राज्यवादी साजिश से सोवियत यूनियन और पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में प्रतिक्रांति हो गई। इस बारे में कॉमरेड मुखर्जी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की गड़बड़ियों और विभिन्न देशों में हुई प्रतिक्रांति की घटनाओं को दिखाकर जिन्होंने यह साबित करना चाहा था कि मार्क्सवाद एक कपोल कल्पना है वे गलती पर थे। क्योंकि इसकी परिणति के लिए मार्क्सवाद जिम्मेदार नहीं है। इसका कारण यह है कि संशोधनवादी ख्रुश्चेव और उनके बाद सीपीएसयू नेतृत्व के द्वारा संशोधनवादी रास्ते का अनुसरण करते जाने के नतीजतन ही यह प्रतिक्रांति हुई है। यह मार्क्सवाद की पराजय नहीं है, बल्कि यह घटना मार्क्सवादी दर्शन की सत्यता और संशोधनवादी भटकाव की घातक परिणति की बात को ही एक बार फिर साबित करती है।

कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने कहा कि कॉमरेड शिवदास घोष की रचनाओं, खासकर आधुनिक संशोधनवाद के बारे में , उसकी उत्पत्ति के बारे में, यह किस तरह एक कम्युनिस्ट पार्टी का वर्ग चरित्र नष्ट कर देता है और किस तरह इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा - इसके बारे में कॉमरेड घोष की शिक्षाओं को पूरी दुनिया के सामने रखने का फैसला पार्टी ने लिया है। 1990 से हमने यह कोशिश शुरू की और इसी बीच हमें इसका अच्छा नतीजा भी मिलने लगा है। विश्वभर में बहुत सी कम्युनिस्ट पार्टियाँ कॉमरेड शिवदास घोष को एक मार्क्सवादी चिन्तनकार के नाते अपना लिया है। यह बात भी उन्होंने मान ली है कि वे मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन और माओ त्से-तुंग के असली उत्तराधिकारी थे और संशोधनवाद से सम्बन्धित उनका अत्यन्त गहन विश्लेषण मार्क्सवादी-लेनिनवादी चिन्तनधारा की एक उन्नत समझ है। कॉमरेड शिवदास घोष की इन शिक्षाओं को प्रयोग करके ही आज संशोधनवाद को परास्त किया जा सकेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की इस गड़बड़ी और समाजवादी देशों में, एक के बाद दूसरे में प्रतिक्रांति होने के समय कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं के आधार पर और दिवंगत महा सचिव कॉमरेड नीहार मुखर्जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने कहा था कि इसमें निराश-हताश होने की कोई बात नहीं है, यह परिस्थिति केवल सामयिक ही है। फिर नये संघर्ष की सोच आयेगी। बुर्जुआ वर्ग आज प्रचार कर रहा है कि 'मार्क्सवाद अकार्यकारी हो गया है।', 'मजदूर वर्ग ने यह त्याग दिया है'। लेकिन पूंजीवाद के तीव्र संकट के कारण लोग बहुत जल्द ही समझ सकेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था उनके जीवन के संकटों को हल नहीं कर सकेगी। लोग फिर अपनी समस्याओं का समाधान तलाशना शुरू करेंगे।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में लोग फिर पूंजीवादी शोषण-उत्पीड़न, साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, शोषण से मुक्ति का रास्ता खोज रहे हैं। भारत में भी परिस्थिति अब अत्यन्त अनुकूल है। अगर हम इस परिस्थिति को ठीक तरह से काम में लगा सके, तो क्रांतिकारी आन्दोलन उत्ताल लहर उठाते हुए आगे बढ़ता जाएगा। अतीत में जो निराशाजनक परिस्थिति दिखाई दे रही थी, आज वह नहीं रही है। 'मजदूरों ने मार्क्सवाद को तिलांजलि दे दी है', या 'मार्क्सवाद-विरोधी लहर उठ खड़ी हुई है–इत्यादि कुप्रचार को मुँह की खानी पड़ी है। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों ही क्षेत्रों में परिस्थिति क्रांति के पक्ष में अत्यन्त अनुकूल है। हमारी पार्टी की दूरदृष्टि बार-बार सही साबित हुई है। कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं के आधार पर पार्टी के नेतृत्व ने इस परिस्थिति के बारे में पहले ही जो मत प्रकट किया था, वह सच साबित हुआ है।

अरब दुनिया की ओर जरा नजर पसार कर देखिये। वहाँ जनता किस तरह स्वेच्छाचारी शासन के खिलाफ लड़ रही है। वहाँ एक के बाद दूसरे देश में स्वेच्छाचारी शासन ढहता जा रहा है। इन सभी मुस्लिम देशों में लोग, यहाँ तक कि महिलाएँ भी भारी संख्या में सड़कों पर उतर आयी हैं। वे हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने कहा कि वे हाल ही में इस्ताबुल गये थे और वहाँ के टीवी में उन्हींने देखा कि किस तरह एक महिला हाथ में झण्डा लिये हुए पुलिस से रूबरू थी और चिल्ला कर कह रही थी कि 'मारो मुझको, मैं अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ , न केवल मेरी खुद की जान, बल्कि मेरे गर्भ में पल रही सन्तान की जान भी देना चाहती हूँ। अविश्वसनीय घटना है! देखिये शोषित-पीड़ित जनता में किस तरह आवेग उफान पर है। इस जन शक्ति को कभी कम करके आँकना ठीक नहीं है। लेकिन सही नेतृत्व और राजनैतिक मार्गदर्शन के अभाव में इतना बड़ा वीरतापूर्ण संघर्ष अपनी सही मंजिल पर नहीं पहुँच पाया। सही क्रांतिकारी नेतृत्व रहता, तो इन सब देशों में पूंजीवाद-विरोधी क्रांति हो गई होती।

समाजवादी खेमे की अनुपस्थिति में जंगखोर साम्राज्यवादियों के युद्ध मनसूबों के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा करने के लिए 1990 में हमारी पार्टी ने दुनिया भर में साम्राज्यवाद-विरोधी जुझारू शांति आन्दोलन गठित करने का आह्वान किया था। साम्राज्यवाद के खिलाफ दुनिया भर में जनता का एकजुट संघर्ष गठित करने और उन संघर्षों को समन्वित, सुसम्बद्ध रूप देने की परिकल्पना हमारी पार्टी की ही थी।

कॉमरेड मुखर्जी ने कहा कि सिंगूर-नंदीग्राम आन्दोलन की ओर नजर डालकर देखिये। हमारी पार्टी की पहल पर ही वहाँ जन कमेटी बनी और शानदार आन्दोलन हुआ। यह आन्दोलन वास्तव में ही ऐतिहासिक था। जवान से लेकर बूढ़े तक सभी लोग इस आन्दोलन में कूद पड़े थे। अधिकारों को बचाने के लिए वे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। आन्दोलन में शिरकत करने वाली महिलाओं से पाशविक ढंग से बलात्कार कर उन्हें कत्ल कर दिया गया, फिर भी वे आन्दोलन को रोक नही पाये। यह आन्दोलन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में किसानों और गरीब खेत-मजदूरों की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। इसके बाद से देश में जहाँ कहीं भी भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश हुई, वहीं लोगों ने सिंगूर-नंदीग्राम की तर्ज पर प्रतिवाद किया। यह देखकर समझा जा सकता है कि हमारे देश में भी लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। भारत में सही विचारधारा लेकर सही क्रांतिकारी पार्टी भी है। लेकिन ताकत के पहलू से अभी हमारी काफी कमजोरी भी है और जरूरत की तुलना में हमारी पार्टी अभी भी छोटी है। इसलिए पार्टी नेतृत्व बार-बार कह रहा है कि हमें और भी संगठक चाहिएं और ये संगठक राजनैतिक और सांगठनिक पहलू से, कम्युनिस्ट चरित्र के पहलू से और क्रांतिकारी वर्ग और पार्टी के प्रति निष्ठा और वफादारी के पहलू से उपयुक्त स्तर के होने चाहिएं। वह दिन दूर नहीं जब भारत की जनता अरब और अफ्रीकी देशों की जनता की तरह ही विक्षोभ आन्दोलन में कूद पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि कॉमरेड्स, आज हमें गहराई से समझना होगा कि क्यों कॉमरेड शिवदास घोष ने एक नई और असली कम्युनिस्ट पार्टी गठित करने के लिए इतना कठिन और कठोर संघर्ष किया था। उन्होंने देश के कोने-कोने में दौरे किये थे, खाने-पीने का जुगाड़ नहीं था, पहनने के लिए उपयुक्त कपड़े भी नहीं थे। फिर भी प्रबल प्रतिकूलता में उनका केवल एक ही सपना था कि यह पार्टी भारत की जनता के मुक्ति संघर्ष में, क्रांति में नेतृत्व देगी। आज यह पार्टी बड़ी हो गई है। देशभर में हम जन आन्दोलन और वर्ग-संघर्ष संगठित कर रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है, वह जरूरत की तुलना में काफी नहीं है। हमें आगे आकर और भी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी और पार्टी व जनआन्दोलन का विस्तार करना होगा

पश्चिम बंगाल की राजनैतिक परिस्थिति के बारे मे उन्होंने कहा कि इस राज्य में सीपीएम ने हमारी पार्टी के द्वारा संगठित किये गये जन आन्दोलनों पर लगातार हमले किये। सिंगूर और नंदीग्राम में इनके इस हमले ने फासीवादी रूप ले लिया था। जनआन्दोलन पर इस फासीवादी हमले को अकेले हमारे अपने बल पर रोकने की स्थिति में अभी हम नहीं थे। इस स्थिति में जनआन्दोलन और वर्ग-संघर्ष को इस हमले से बचाने के लिए यह जानते हुए भी कि तृणमूल कांग्रेस एक दक्षिणपंथी पार्टी है, उसके साथ वक्ती तौर पर हमने हाथ मिलाया। किसी भी एक खास मुहूर्त में जब कोई दक्षिणपंथी ताकत जनता के मुख्य दुश्मन के खिलाफ लड़ती है, वह ताकत पूंजीपतियों की अत्यन्त भरोसेमंद होने पर भी एक क्रांतिकारी पार्टी उसके साथ एकता करती है। यह बात सच है कि इस आन्दोलन को आधार करके तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता काफी बढ़ गई और ममता बैनर्जी भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आ गई। उनकी जीत की सम्भावना भांपकर पूंजीपति वर्ग और कार्पोरेट घराने उसके पीछे आ खड़े हुए हैं। यह पूंजीपति वर्ग चूँकि हमारी पार्टी को अपना दुश्मन मानता है इसलिए ममता बैनर्जी के साथ हमारे गठबंधन को अच्छी निगाहों से नहीं देखता है। वे तृणमूल कांग्रेस पर दबाव डालते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सीट समझौते के द्वारा यह दबाव साफ जाहिर हो गया है। उन्होंने हमें 14 बार चुनावों में 12 बार जीती हुई दो सीटें जयनगर और कुलतली को छोड़कर और कोई सीट नहीं दी। दरअसल हमें कोई भी सीट नहीं दी गई। इसके बावजूद जनआन्दोलन के स्वार्थ में सीपीएम को परास्त करने के लिए हमने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कहीं कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करने की बात ऐलानिया तौर पर कही। हम सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो ध्रुवीकरण हो गया है वह नकारात्मक ध्रुवीकरण है, जो सीपीएम को हटाने के नतीजतन पैदा हुआ है। सीपीएम को परास्त करना ही इस ध्रुवीकरण का उद्देश्य है। यही घटना सारे भारत में घट रही है। हर जगह लोग देख रहे है कि बुर्जुआ पार्टियों या नकली वामपंथी पार्टियों में से कोई भी राजनैतिक पार्टी विश्वास करने लायक नहीं है। इसके बावजूद नगेटिव ध्रुवीकरण की वजह से कभी यह पार्टी कभी वह जीतकर सत्ता हथिया रही है।

उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि संसद या विधानसभा एक बुर्जुआ प्रतिष्ठान है, जिससे जनजीवन की किसी भी बुनियादी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जबकि इन प्रतिष्ठानों के प्रति लोगों में मोह बचा हुआ है। विधानसभा, संसद में वर्ग-संघर्ष और जनआन्दोलन की आवाज बुलन्द करने के लिए चुनावों में क्रांतिकारी भाग लेते हैं जो जनआन्दोलन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा संसद के मोह से जनता को मुक्त करना भी इसका उद्देश्य है। जब तक इस मोह से मुक्त नहीं हो जाते तब तक जनआन्दोलन की ताकत वोट के विकल्प के तौर पर प्रतिष्ठित नहीं होगी। इस मोह से मुक्त किये बिना चुनावों के द्वारा किसी भी क्रांतिकारी ताकत का सत्ता का अधिकारी होना बहुत मुश्किल है। हालाँकि जनता अगर इस मोह से मुक्त हो जाये, तो फिर चुनाव में हिस्सा लेने की जरूरत नही रहती है। तब क्रांति का वह आकाँक्षित मुहूर्त आ जाता है।

कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने कहा कि पूंजीवाद और अधिक टिक नहीं पायेगा, चाहे कितना ही वह भूमण्डलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण कर ले। कोई भी भ्रम-भ्रान्ति फैलाकर वह जनता को आन्दोलन करने से और रोक नहीं सकेगा। इस परिस्थिति में जनआन्दोलन में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) का नेतृत्व कायम करना है, तो जनआन्दोलन की जबरदस्त लहर पैदा करनी होगी और हम पूंजीवाद को उखाड़ फेंककर समाजवाद कायम कर पायेंगे। इसके लिए कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं को बारीकी से अध्ययन-मनन करने और अपनाने की जरूरत है। हमें संघर्ष को और भी उन्नत कर अच्छे कम्युनिस्ट के रूप में खुद को ढालना होगा, कॉमरेड शिवदास घोष के योग्य शिष्य बनना होगा। जनता में हमें जाना होगा, उनके बीच हमें रहना होगा, उनसे हमें सीखना होगा और उन्नत रूचि-संस्कृति और नीति-नैतिकता के आधार पर जनआन्दोलन गठित करना होगा। पूराने वर्ग की सोच-विचार व आदत-आचरण का जो कुछ अवशेष बचा हुआ है उसे जड़ से उखाड़ फेंक कर मजदूर वर्ग का चरित्र लेकर अपना खुद का नवनिर्माण करना होगा। सचेत रूप से हमें यह संघर्ष चलाना होगा। तभी 24 अप्रैल मनाना सार्थक होगा। ■■

मुरादाबाद में ऑटो रिक्शा चालकों का आन्दोलन

लम्बे समय ये अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन चला रहे मुरादाबाद ऑटो रिक्शा चालकों की एक विशाल सभा ईदगाह मैदान मुरादाबाद में एआईडीवाईओ के बैनर तले हुई। इसमें सैकड़ों की तादाद में अपने वाहनों साहित ऑटो चालकों ने हिस्सा लिया सभा को एआईडीवाईओ के प्रान्तीय अध्यक्ष कॉमरेड हर किशोर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज समय का तकाजा है कि हम सब संगठित हो अपने ऊपर हो रहे हर प्रकार के शोषण जुल्म के खिलाफ आवाज बुलन्द करें और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष तेज करें। उन्होंने आगे कहा कि इस महंगाई के दौर में वैसे ही जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। ऑटो चालकों से ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ दफ्तर, नगर निगम व गुंडे लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। इसका संगठित होकर प्रतिरोध करना जरूरी है। सभा के उपरान्त नौ सूत्रीय मांगों को लेकर 13 मई को ही जिलाधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सिटमजिस्ट्रेट श्री हरिकृष्ण नाथ त्रिपाठी से संगठन के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होनी तय हुई। वार्ता के दौरान ये मांगें मान ली गयी।

1. तय हुआ कि आटो चालकों से अवैद्य वसूली पर रोक लगायी जायेगी। 2. आरटीओ दफ्तर तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न तुरन्त बन्द होगा 3. ऑटो चालक कम दूरी के लिये 5 रुपया और लम्बी दूरी के लिए 10 रु. किराया वसूल कर सकेंगे। 4. एक आटो में चार सवारी बैठाने की आटो चालकों को छूट होगी। 5. रूट निर्धारण नही किया जायेगा। 6. बिना उचित कारण के मनमाने तरीके से ऑटो चालकों के चालान नहीं किये जायेंगे और भारी जुर्माना नहीं डाला जाएगा। 7. ऑटो चालकों के कैम्प लगाकर लाइसैन्स, टैक्स आदि की सभी समस्यायें दूर की जायेंगी। 8. सभी इच्छुक बालिग पढ़े-लिखे, अनपढ़ चालकों के डीएल तुरन्त बनाये जायेंगे। 9. सीएनजी गैस वितरण में हो रही धांधली को तुरन्त रोका जायेगा।

इस प्रकार संगठन के नेतृत्व में सभी मांगें पूरी होने से ऑटो चालकों में बहुत उत्साह बना हुआ है। संगठन के नेतृत्व में संघर्ष के लिये तैयार हैं। प्रशासन के साथ हुई वार्ता में-कॉमरेड हरकिशोर सिंह, मौ. गौरी, राकेश चौहान, शरीफ अहमद, शाकिर भाई, मानसिह सैनी, मौ. आलम, प्रदीप चौधरी आदि शामिल थे।

उ.प्र. में किसानों पर हुई पुलिस फायरिंग पर एसयूसीआई(सी) ने रोष जताया

सुलतानपुर, 9 मई। सोशलिस्ट युनिटी सेन्टर आफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की सुलतानपुर जिला कमेटी का एक प्रतिनिधि मण्डल जिला सचिव कॉमरेड जगन्नाथ वर्मा के नेतृत्व में आज अपरान्ह 1 बजे जिला अधिकारी से मिला और ग्रेटर नोएडा के किसानों पर किये गये बर्बर हमले के खिलाफ महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में पुलिस के बर्बर हमले की निन्दा करते हुए मृतकों के परिवार जनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने, घायलों को समुचित इलाज करने व 1 लाख रुपये मुआवजा देने, फायरिंग के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करने, किसानों की मांग के अनुसार जमीन का मुआवजा देने, उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण बन्द करने, गंगा एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस वे, टाउन शिप बनाने की सभी योजनाएं एवं किसान विरोधी सेज नीति रद्ध करने की मांग की गई है। प्रतिनिधि मण्डल ने किसानों की लड़ाई को जायज बताया ओर प्रतिनिधि मंडल मं रामचन्द्र मौर्य, केदारनाथ पाल, जयप्रकाश मौर्य, रामकृपाल मौर्य, राजेन्द्र प्रसाद मौर्य, मनोज कुमार वर्मा, रामकुमार यादव, विजयानन्द तिवारी, करुणाशंकर तिवारी आदि प्रमुख लोग शामिल थे।

एसयूसीआई(सी) पार्टी द्वारा 8 मई को इलाहाबाद में बालसन चौराहे पर मुख्यमंत्री मायावती का पुतला फूंका गया, सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के खिलाफ नारे लगाये और किसानों पर गोलीबारी की निन्दा की। जौनपुर जिला में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी को माँगों का ज्ञापन सौंपकर अपना रोष जताया। मुरादाबाद, कानपुर, प्रताप गढ़ जिलों में भी इस घटना को जोददार विरोध किया गया।

बेरोजगारी के विरुद्ध युवा सम्मेलन

पिलानी (राजस्थान) : बढ़ती बेरोजगारी, सांस्कृतिक पतन व भ्रष्टाचार आदि जीवन के ज्वलन्त मुद्दों के खिलाफ यहाँ सरावगी गेस्ट हाउस में 13 मई को एआईडीवाईओ के तत्वावधान मे युवा सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता एआईडीवाईओ के राज्य सचिव कॉमरेड शंकर दहिया ने की। मुख्य अतिथि एआईडीवाईओ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड प्रतिभा नायक थी। सम्मेलन में उनके इलावा एआईडीएसओ के राज्य सचिव कॉमरेड राजमल शर्मा और तमिलनाडु के एआईडीवाईओ के कॉमरेड एम.जी. गणेशन भी मंच पर उपस्थित थे।

वक्ताओं ने कहा कि बेरोजगारी आदि समस्याओं की जड़ यह शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था है। वोटों के जरिए सरकार बदल कर नहीं बल्कि क्रांति के जरिए इस शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था को हटाकर इसकी जगह शोषणहीन समाजवादी व्यवस्था कायम करके ही मुकम्मल तौर पर इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तब तक राहत पाने के लिए सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ उन्नत नीति-नैतिकता के आधार पर जोरदार युवा आन्दोलन गठित करने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया। सम्मेलन में कॉमरेड सरदार राम, सुभाष, राजु लुहार, डॉ. रविकान्त शर्मा, संतोष दहिया, सुमन गहलौत, राजेन्द्र सिहाग, राकेश आलड़िया, मनोज नायक समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए।

एसयूसीआई (सी) उड़ीसा के बेदखली-विरोधी आन्दोलन में शामिल

दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय कम्पनी पोस्को से उड़ीसा सरकार के हुए एमओयू को रद्द करने, पोस्को के लिए भूमि अधिग्रहण करना बंद करने, केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण से छेड़-छाड़ पर रोक लगायी जाने आदि माँगों को लेकर 23 अप्रैल को उड़ीसा प्रतिवाद दिवस मनाया गया। इन माँगों पर 18 मई को भुवनेश्वर में संयुक्त विरोध प्रदर्शन में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), सीपीआई-एमएल (लिबरेशन), सीपीआई-एमएल-न्यू डेमोक्रेसी आदि वामपंथी पार्टियां शामिल हुई। राज्यपाल को इन पार्टियों के नेताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।

महिलाओं की गायन व खेल-कूद प्रतियोगिता

दिल्ली: एआईडीवाईओ तथा अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन की शालीमार बाग इकाई द्वारा 8 मई को महिलाओं के लिए गायन, म्युजिकल चेयर तथा 100 मी. की केला दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनमें इलाके की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। प्रो. नरेन्द्र शर्मा (संयोजक, मनीषी व शहीद यादगार समिति), श्रीमति सुबोध शर्मा (अध्यक्ष, एआईएमएसएस, दिल्ली) तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक प्रतियोगिता में जीतने वाली महिलाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार व कुछ सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किये गये। साथ ही एक सभा का आयोजन भी किया गया जिसमें 'वर्तमान समय में सामाजिक समस्याओं के समाधान में महिलाओं की भूमिका' विषय पर चर्चा हुई।

सभा को कॉमरेड प्रताप सामल(सचिव, एसयूसीआई(सी), दिल्ली), नीतु खन्ना(इंचार्ज, एआईएमएसएस, शालीमार बाग)तथा प्रकाश देवी (राज्य सचिव, एआईडीवाईओ)ने सम्बोधित किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री को ज्ञापन

सोनिया विहार क्षेत्र में दूषित जल से होने वाली बीमारी पीलिया फैलने के खिलाफ महिला सांस्कृतितक संगठन की सोनिया विहार इकाई द्वारा गत दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के साथ के गणमान्य नागरिकों के लगभग 500 हस्ताक्षर संलग्न किए गए हैं। जिन्हें सोनिया बिहार इकाई अध्यक्ष अर्चना शर्मा एव सचिव पुष्पा चमोली के नेतृत्व में इकट्ठा किया गया।

ज्ञापन में शोधित जल की आपूर्ति, पीलिया की रोकथाम के लिए टीकाकरण, सचल चिकित्सालय एवं घरेलू पेयजल व्यवस्था की मांग की गई है। इसके अलावा क्षेत्र में 100 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने की मांग भी की गई है।

अमूल दूध के दामों में वृद्धि के खिलाफ गुजरात में एसयूसीआई(सी) द्वारा प्रदर्शन

भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन...

(पृष्ठ 2 का शेष)

पर आन्दोलन जितना तेज होता जाएगा, भ्रष्टाचार के सरगनों, बुरा काम करने वालों और रुपये ऐंठने वालों का उतना ही ज्यादा जोरशोर से प्रतिरोध किया जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जो लोग गंभीर हैं उन्हें इस छिपी हुई सच्चाई को गहराई से समझना होगा।

जनआन्दोलन की बढ़ोतरी में अड़चन

अगला सवाल यह है कि जनवादी आन्दोलनों की वांछित बढ़ोतरी देशभर में क्यों नहीं हो पा रही है? इसका जवाब ढूँढने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। विधानपालिका के भीतर, न तो सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार से मुक्त है और न ही विपक्ष जो कि चुनावी उलटफेरों के नतीजतन बारी-बारी से अपनी अपनी भूमिका अक्सर बदलते रहते हैं। उल्टे, वे खुद ही भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबे हुए हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर वे अपना घर भरने के लिए, आत्म संवर्धन के लिए एक दूसरे से सांठ-गांठ कर सरकारी प्रशासन में भ्रष्टाचार और हर तरह के गलत काम करने वालों को शह दे रहे हैं। बुर्जुआ पार्टियों के तो कहने ही क्या, यहाँ तक कि सीपीआई(एम), सीपीआई जैसी नकली मार्क्सवादी पार्टियाँ भी इस श्रेणी में आ गिरी हैं। उन्होंने न केवल संसद से बाहर होने वाले आन्दोलनों को तिलांजलि दे दी है, बल्कि लोग दिखावा मीडिया के प्रचार में विरोध का नाटक करने के सिवाय इस सवाल पर विधानपालिका में भी बराबर चुप्पी साधे रहती हैं। बुर्जुआ राजनीतिज्ञों की तरह, ये नकली मार्क्सवादी भी शासक पूंजीपति वर्ग की खुशामद करके सत्ता की मौज लेने में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और जहाँ कल तक सत्ता में थे उन राज्यों में क्रूरता से जनआन्दोलनों को कुचलते रहे हैं। साथ ही, पुलिस-प्रशासन-तश्कर-अपराधी-बेईमान व्यापारी-कार्पोरेट लोबिस्ट-पार्टी कार्यकर्ताओं का नापाक गंठजोड़ करने के रास्ते सत्ता में बने रहने के अपने प्रयास में वे भी व्यापक तौर पर फैले भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में दूसरा और कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ गन्दगी और कूड़ा-कर्कट जमा होगा वहाँ से जहरीली गैसें निकलनी ही हैं और विषैले वायरस पैदा होने ही हैं। अगर कोई उस गन्दगी के गर्त में कूदता है, तो वह उससे बच नहीं सकता है। काजल की कोठरी में काला हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार यह बात साफ जाहिर है कि चूँकि बढ़ते भ्रष्टाचार के प्रकोप के कारगर प्रतिरोधक जोरदार जन आन्दोलन वांछित पैमाने पर विकसित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये अपना-अपना स्वार्थ देखने वाले, भ्रष्ट और अत्यन्त अनैतिक व्यक्ति शासकवर्ग की सरपरस्ती में पनपते जा रहे हैं। इसलिए आये दिन नये-नये घोटालों का भण्डाफोड़ हो रहा है। देश को बंधक बना कर रखने वाले नये-नये सकेण्डलों से पर्दा उठ रहा है। ताजातरीन रहस्योद्घाटन 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर है जिसने दिखाया कि कितने बड़े पैमाने पर संस्थानीकृत भ्रष्टाचार लोगों को ठग रहा है।

अन्ना हजारे का आन्दोलन और जन लोकपाल बिल

यह पृष्ठभूमि है जिसमें गांधीवादी नजरिये वाले अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार खत्म करने के तरीके की अपनी खुद की समझ के अनुसार सरकार और प्रशासन में भ्रष्टाचार के दोषियों को गिरफ्तार कर सजा देने के लिए एक समग्र भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल (ऑमबड्समैन) कानून तुरन्त बनाने के लिए आन्दोलन छेड़ा। लोकपाल की धारणा जिसका मतलब है 'जनता का रक्षक' 1960 के दशक में जनता के दबाव मे आयी थी ताकि उस समय की भारतीय शासन-व्यवस्था में सत्ता के ऊँचे गलियारों में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सके। पहला लोकपाल बिल कथित रूप से चुने हुए नुमाइन्दों को सेन्सर करने की आम आदमी को सीधे शक्तियाँ देने के आशय से 1969 में चौथी लोकसभा में पास हो गया था लेकिन राज्य सभा में पारित नहीं हो सका। यह तब से यह लम्बित पड़ा है। अन्ना हजारे और उनके अनुयायी दावे के साथ कहते हैं कि सरकारी लोकपाल बिल में कई कमजोरियाँ हैं और इसलिए उन्होंने संशोधित जन लोकपाल (सिटीजन ऑमबड्समैन) बिल प्रस्तावित किया है, जो इस तरह से बनाया गया है कि लोकपाल को जो कोई दोषी पाया जाये उसके खिलाफ अपनी खुद की ओर से या आम जनता से भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर कार्रवाई शुरू करने या सजा देने की शक्ति प्रदान करता है। लोकपाल के पास उनके मतानुसार पुलिस की शक्तियाँ होनी चाहिएँ और उसे एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करना चाहिएं। लोकपाल के सदस्य न्यायधीशों, नागरिकों और संवैधानिक ऑथोरिटियों से छांटे जाने चाहिए न कि राजनीतिज्ञों से। अन्ना हजारे ने माँग की है कि सरकार और आन्दोलन के संगठनों द्वारा मनोनीत सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों, दोनों से सदस्य लेकर गठित एक संयुक्त कमेटी द्वारा इस बिल का प्रारूप तैयार किया जाए।

यह बहुत ही जनवादी माँग रही है और इसलिए इसे सभी ईमानदार लोगों का अनुमोदन भी मिला। हमारी पार्टी ने भी इसकी ताइद की। अन्ना हजारे देश की राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठे और देश के विभिन्न भागों में लोगों ने उनके आन्दोलन के समर्थन में धरने-प्रदर्शन व रैलियाँ की। यह साफ जाहिर है कि जन जीवन में तबाही मचाने वाले संस्थानीकृत भ्रष्टाचार को लोग अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। लेकिन यह समझना अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो इस आन्दोलन में नदारद है। यह सच है कि जनवादी आन्दोलन के मंच से मौजूदा कानूनों में सुधारों और परिवर्तनों की माँगें उठायी गई हैं ताकि दु:ख पाये लोगों के लिए कुछ राहत हासिल की जा सके, भले ही वह अस्थायी हो। इस नुक्ते नजर से प्रस्तावित जनलोकपाल बिल भी न्यायोचितता रखता है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए। बढ़ते भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम लगाने के किसी भी उचित प्रावधान वाला कोई भी विधि-विधान, कानून बनाने का सदा स्वागत है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि यह संशोधित जन लोकपाल बिल एक बार कानून बन गया तो यह मामला हल हो जाएगा यह हकीकत से मेल खाने वाली बात कदापि नहीं होगी। इस लाइन पर किसी भी सोच का अन्त सुधारवाद में होगा और इस भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन को इसकी तार्किक मंजिल पर नहीं ले जा सकेगा।

क्या केवल कानूनी उपायों से भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है

जनता के दबाव में कुछेक अच्छे कानून बने हैं। लेकिन, यह देखा गया है कि ऐसे कानूनों का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुँचा है क्योंकि इन कानूनों को लागू करने वाली मशीनरी वास्तव में काम नहीं करती है। इस बुर्जुआ व्यवस्था में, विधान पालिकाओं में कानून बनाये जाते हैं और कार्यपालिका की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन कानूनों को लागू करे और न्यायपालिका का काम है कि सुनिश्चित रूप से कानून बकायदा और समान रूप से लागू करवाये। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में, कार्यान्वयन की ये दोनों ही शाखाएं वर्ग दृष्टिकोण से न तो मुक्त हो सकती हैं और न ही मुक्त हैं। फिर भी बड़े लम्बे चौड़े दावे करते हैं कि बुर्जुआ कानून की नजरों में सभी समान हैं, जबकि हकीकत इसके एकदम विपरीत है। कानून अपना काम नहीं करता बल्कि इस विद्यमान पूंजीवादी व्यवस्था में भेदभावपूर्ण अमल करने को बाध्य है क्योंकि अमल करने वाली मशीनरी निष्पक्ष नहीं है जैसा कि बताया गया है बल्कि शासक वर्ग-परस्त रवैया और पूंजीवादी व्यवस्था के रखवालों को बचाने की तरफ झुकाव दर्शाती है। जैसा कि हमने पहले दिखाया पतनशील मरणासन्न पूंजीवाद न्याय पर अन्याय, नियम-कानूनों के पालन पर नियम-कानूनों को तोड़ने का प्राधान्य प्रदान किये बिना जिन्दा नहीं रह सकता। यही वजह है कि उच्च स्तर पर कानून-कायदों को तोड़ने वाले उनका कोई बाल भी बाँका हुए बगैर बच निकलते हैं क्योकि वे ही तो जिन्दा रहने के लिए हांफ रहे पूजीवाद के आखिरी सहारे हैं। थोड़ी सी व्याख्या करके समझाने ये यह हकीकत और भी साफ उजागर हो जाएगी। यह कोई रहस्य नहीं रह गया है कि समूचा प्रशासन सिर से पांव तक भ्रष्ट है। यहाँ तक कि न्यायपालिका जिसे जनसाधारण अन्तिम राहत के लिए आशा की नजर से देखते हैं उस पर भी आज भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ठीक उस समय जब घोटालों के भण्डाफोड़ ने बुर्जुआ राजनीतिक वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों में निरंकुश भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार व्याप्त होने की सकते में डालने वाली स्पष्ट स्वीकृति से उच्चतर न्यायपालिका में बढ़ते भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला है। यहाँ तक कि रुपयों के बदले में फैसले बदलने के भी आरोप लगे हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस पर भाई-भतीजावाद और गलत काम करने का दोषारोपण किया गया है। न्यायविदों का एक हिस्सा ठीक ही यह सोचता है कि एक जज के लिए ईमानदारी और निष्पक्षता के ऐसे स्टैण्डर्डों से गिर जाना उन पर जताये गये विश्वास से विश्वासघात करना है।

कोई भी बहाना या कोई कानूनी सापेक्षता ऐसे विश्वासघात को माफ नहीं कर सकती। इन्साफ के नजरिए से रिश्वत का आकार या भ्रष्टाचार का दायरा कितना है यह एक जज को नापने-तोलने का पैमाना नहीं हो सकता। उसे खुद को सन्देह से पूर्णतया ऊपर रखना चाहिए। इन सब आरोपों और आलोचनाओं से यह साफ है कि न्यायपालिका कुछ ऐसी करतूत कर रही है जो न्याय देने की प्रक्रिया को ही जोखिम मे डाल रही है।

जब वस्तुगत वास्तविकता ऐसी है, तो गयी-बीती हो चुकी सड़ांध मारने वाली पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने से जुदा महज एक कानूनी या संस्थागत सुधार क्या प्रशासन या सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकेगा ? क्या गारन्टी है कि न्यायपालिका के एक हिस्से की तरह, लोकपाल खुद भ्रष्टाचार के वायरस से ग्रस्त नहीं होगा ?

यह तजुर्बा हो चुका है कि सुधारवादी आन्दोलनों के प्रायोजक जो घिसी-पिटी पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली किसी बुनियादी समस्या का स्थायी समाधान विद्यमान कानूनी व्यवस्था की चारदीवारी में ही तलाशना चाहते हैं, वे इस व्यवस्था की इस विपथगामी भूमिका के प्रति उदासीन पाये जाते हैं। या तो वे इसके बारे में अनभिज्ञ हैं या शासक पूंजीवाद को गलत तरीके से परेशान नहीं करना चाहते। साफ जाहिर है कि ऐसे किसी सुधारवादी आन्दोलन जो आन्दोलन पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के सवाल को नजरअंदाज कर देता है, उसके नतीजे के तौर पर भ्रष्टाचार कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा, उल्टे यह बुर्जुआ कानूनी-प्राशसनिक ढाँचे के बारे में भ्रम पैदा करेगा। अन्ना हजारे और उसके अनुयायी जैसा कि देखा गया है यह सोचते हैं कि कानूनी सुधारों से व्यवस्था साफ-सुथरी बनायी जा सकती है। चूँकि अन्ना हजारे और जन लोकपाल बिल आन्दोलन के अन्य प्रायोजक गांधीवादी दर्शन के अनुयायी होने का दावा करते हैं, उनसे यह आशा नहीं की जाती है कि उनमें से कई लोगों की ईमानदारी और संजीदगी के बावजूद वे इस सुधारवादी रवैये के सिवाय कुछ और रवैया दिखायेंगे। इसलिए अन्ना हजारे का आन्दोलन प्रतिक्रियावादी पूंजीवादी की ढाल बन गया है और पहले से ही यह मानकर कि संस्थानीकृत भ्रष्टाचार के उन्मूलन की रामबाण दवा जन लोकपाल बिल बनाना है, इसे बनवाने पर जोर दिया है। इसके अलावा, जब कोई व्यक्ति भूख हड़ताल का सहारा लेता है, यह उस व्यक्ति को तो हीरो बना देती है लेकिन यह आन्दोलन की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देती है क्योंकि सारा ध्यान व्यक्ति की व्यक्तिगत कारगुजारी की ओर फेर दिया जाता है और इस प्रकार मुख्य मुद्दे को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि इस लोकपाल बिल आन्दोलन के मामले में सरकार का प्रत्युत्तर गौरतलब है और आँखें खोलने वाला है। अन्ना हजारे के आन्दोलन के दौरान जितनी भी थोड़ी-बहुत जन प्रतिरोध की भावना उभर कर सामने आयी, निस्सन्देह उसने निहित स्वार्थ के हलकों को हिला कर रख दिया क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि कोई संस्थागत सुधार भी उनकी बेलगाम लूट-खसोट में एक अड़चन के रूप में आड़े आ सकता है। साथ ही, अपने वर्ग की सहज प्रवृत्ति से उन्होंने भांप लिया कि ऐसे सुधारवादी आन्दोलन पूंजीवादी की सड़-गल रही लाश को ढकने और इसके असली कारण से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ फेरने में बड़ी भारी मदद करेंगे। इसलिए चाहे सत्ता में जो भी हो, सत्ताधारियों की ओर से प्रयास यह रहा कि इस आन्दोलन को बढ़चढ़कर प्रचार मिले और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सही आन्दोलन के रूप में बढ़ाचढ़ाकर दिखाया जाये। तब कई बड़े-बड़े घोटालों और सकेण्डलों में फंसी काफी नोंक-झोंक और हीले हवालों के बाद कांग्रेस-नीत केन्द्रीय सरकार अन्ना हजारे के मनोनीत सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से मिलकर इस बिल का प्रारूप तैयार करने पर राजी हो गई। लेकिन थोड़े ही

(शेष पृष्ठ 7 पर)

आजादी आंदोलन की प्रथम महिला शहीद प्रीतिलता वाद्देदार का जन्म शताब्दी वर्ष सम्मानपूर्वक मनाया गया

दिल्ली में जनसभा : एआईएमएसएस, दिल्ली की बुराड़ी शाखा द्वारा शहीद प्रीतिलता वाद्देदार के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 'महिला स्पोर्ट्स' और जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें स्थानीय महिलाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। सभा को एआईएमएसएस दिल्ली की उपाध्यक्ष कॉ. शुभा दीक्षित, संयोजक कॉ. रितु कौशिक, बुराड़ी इंचार्ज कॉ. मीरा चौरसिया तथा कॉ. आशा रानी ने संबोधित किया। सभा को मुख्य वक्ता के तौर पर एसयूसीआई (सी) की दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. मैनेजर चौरसिया ने संबोधित किया। उन्होंने सरकार द्वारा पानी के निजीकरण तथा राशन व्यवस्था में धांधली के खिलाफ एसयूसीआई (सी) पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने और आंदोलन को व्यापक बनाने का आह्वान किया।

सभा के अंत में खेल प्रतियोगिता में विजयी महिला प्रतिभोगियों को इनाम के तौर पर कार्यक्रम के स्मृति चिह्न प्रदान किए गए।

गुना (म.प्र.) में काव्य गोष्ठी : अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन की गुना इकाई के द्वारा एक काव्य संध्या स्थानीय आदर्श कॉलोनी स्थित आज़ाद पार्क में आयोजित की गई। इसमें कवियित्री श्रीमती नीलम कुलश्रेष्ठ, डॉ. रश्मि चौधरी, विक्की श्रीवास्तव, सुश्री संगीता जैन व श्रीमती रंजना कोठरी ने अपनी कविताएँ प्रस्तुत की।

काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महिला सांस्कृतिक संगठन की जिलाध्यक्ष रचना अग्रवाल ने कहा कि क्रांतिकारी प्रीतिलता वाद्देदार के जीवन-संघर्ष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज के विकास में नारियों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के आयोजन में अपनी भागीदारी करनी चाहिए।

गुना (म.प्र.) क्रांतिकारी प्रीतिलता वाद्देदार की याद में स्मृति सभा : अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन की गुना इकाई द्वारा 18 अप्रैल को यहाँ एक स्मृति सभा दुर्गा कॉलोनी में आयोजित की गई।

कार्यक्रम में क्रांतिकारी गीतों के साथ प्रीतिलता वाद्देदार को याद किया गया। संगठन की जिला उपाध्यक्ष कॉमरेड विक्की श्रीवास्तव ने कहा कि आजादी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी की थी, जिनमें से एक उज्ज्वल नाम प्रीतिलता वाद्देदार का है। उन्होंने अल्पायु में इतना बड़ा संघर्ष किया और अंग्रेजो के खिलाफ सशस्त्र कार्यवाही में शामिल हुई। उनके जीवन से आज सभी महिलाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता हैं और वर्तमान समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। संगठन की जिला सचिव कॉमरेड संगीता आर.वी. ने अपने वक्तव्य में महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला और क्रांतिकारी प्रीतिलता के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर समस्त समस्याओं के समाधान के लिए जन आन्दोलन रास्ते को ही एकमात्र तरीका बताया। अश्लीलता, अपसंस्कृति और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ महिलाओं से एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संगठन की जिला अध्यक्ष कॉ. रचना अग्रवाल उपस्थित थी। कॉलोनी की महिलाओं ने भी शिरकत की। सभा का संचालन संगठन की सदस ललिता अग्रवाल ने किया एवं सीमा राय ने आभार माना।

गुना में समेस्टर सिस्टम के खिलाफ छात्र कन्वेन्शन

गुना: छात्रों के संयुक्त मंच एन्टी सेमेस्टर फोरम ने 1 मई को स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ जिला स्तरीय छात्र कन्वेंशन आयोजित किया। कन्वेंशन की शुरुआत में सोनम शर्मा ने प्रस्ताव का वाचन किया। प्रस्ताव पर विभिन्न तहसीलों के कॉलेज के छात्रों ने सेमेस्टर के दुष्प्रभाव पर बात रखी। एन्टी सेमेस्टर फारेम के क्षेत्रीय संयोजक सचिन जैन ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व यशपाल कमेटी की सिफारिशों के तहत जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की है उससे शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण को बढ़ावा मिला है। एन्टी सेमेस्टर फोरम के प्रदेश संयोजक तथा कन्वेंशन के मुख्य वक्ता मुदित भटनागर ने कहा कि सेमेस्टर प्रणाली छात्रों की तार्किक मानसिकता को खत्म कर रही है। परीक्षाओं के चलते छात्रों को समाज के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है। सरकार प्रचार माध्यमों से अश्लीलता-अपसंस्कृति भी फैला रही है ताकि छात्रों की नैतिक रीढ़ टूट जाए। भटनागर ने सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ जोरदार आन्दोलन की अपील की। कन्वेंशन के अंत में जिला स्तरीय कमेटी में जिला संयोजक सचिन जैन तथा सह संयोजक अजीत सिंह सहित छः सदस्यीय संयोजन समिति तथा 24 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई। कन्वेंशन में सैकडों की संख्या में छात्रों सहित शहर के वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित रहे। कन्वेंशन का संचालन अजीत सिंह ने किया।

भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन...

(पृष्ठ 6 का शेष)

समय में सरकार ने कानून पर मतभेद दिखाने या संसद में इसके पारित होने को टालने के लिए कई वाहियात के सवाल उठाने शुरू कर दिये। सारा प्रयास इस बात के लिए था कि लोकपाल बिल के मुद्दे को जिन्दा रखा जाये, विशुद्ध रूप से कानूनी नुक्ते नजर से इसके हक में या इसके खिलाफ कुछ बेबात की चर्चा को बढ़ावा दिया जाये, विभिन्न तरह के देरी करने वाले हथकण्डे अपना कर इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लम्बा किया जाये जनमानस को कानूनियत का चारदीवारी तक ही सीमित करके रखा जाये और इस प्रकार लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सही रास्ते पर देशव्यापी दीर्घकालिक ताकतवर आन्दोलन के रास्ते से दूर रखा जाये।

यह एक बार फिर दोहरा दें कि जब तक सरकार पर दीर्घस्थायी जनआन्दोलन का एक लगातार दबाव नहीं होगा, तब तक बनाये गये कानूनों पर अमल भी नहीं होगा। कड़े प्रावधान वाले ऐसे तमाम कानून एक रद्दी कागज के पुलिन्दे के सिवाय और कुछ नहीं होंगे। इसी तरह, कोई सुधार करवाने के लिए उठाया जाने वाला कोई कदम अगर समस्या की जड़ से अलग करके देखा जाये और जनआन्दोलन द्वारा उसका समर्थन नहीं किया जाये, तो इसका अन्त एक खामखा की कवायद जैसा ही होगा।

जनआन्दोलन ही है कारगर बचाव

दुःख-तकलीफ से ग्रस्त लोगों को यह समझने की जरूरत है कि इस दमनकारी भ्रष्ट पूंजीवादी व्यवस्था में जीवन-अजीविका की कोई भी माँग उन्नत नीति-नैतिकता और संस्कृति के आधार पर संगठित जनवादी जनआन्दोलन निर्मित किये बिना और इसे पूँजीवाद-विरोधी क्रांतिकारी संघर्ष से जोड़े बिना हासिल नहीं की जा सकती। इस बात का कोई भी भ्रम नहीं रहना चाहिए कि महज एक विधि-विधान लाकर राज्य शासन व्यवस्था या प्रशासन को व्यापक पैमाने पर फैलते जा रहे भ्रष्टाचार के चुँगल से पूरी तरह मुक्त किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, पूंजीवाद से पैदा होने वाली सभी पथभ्रष्टताओं और खतरों से छुटकारा वोटों से सरकार बदलकर पाया जा सकता है यह उम्मीद करना व्यर्थ है। वोट से हम जितना ही समस्याओं से निजात पाने की सोच रहे हैं, उतना ही हम निराशा-हताशा में डूबते जा रहे हैं क्योंकि वान्छित राहत या छुटकारा हमेशा मृग मरीचिका बना रहा है। एक पार्टी या गठबंधन की जगह दूसरा आ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुक पा रहा है, बल्कि उल्टे और भी बढ़ गया है। आन्दोलन का रास्ता छोड़ देना हर कदम पर महंगा साबित हो रहा है। इसलिए लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ तीव्र आन्दोलन विकसित करने का साफ ध्येय लेकर कदम उठाना चाहिए जो व्यापकतर पूंजीवाद-विरोधी क्रांतिकारी आन्दोलन के परिपूरक होना चाहिए। इस उभरते हुए जन आन्दोलन का समर्थन जब तक सुधार की माँग के पीछे नहीं हो, तब तक शासकों के अनिच्छुक हाथों से सुधार की कोई भी माँग छीनी नहीं जा सकती। साथ ही कार्यान्वयन करने वाली मशीनरी से भी जन आन्दोलन के दबाव, कड़ी निगरानी और सतर्कता के बिना बनाये गये दिशा निर्देशों के मुताबिक कुछ हद तक भी कार्य नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए जीवन की ज्वलन्त समस्याओं पर जोरदार आन्दोलन विकसित करने के साथ कदम ताल मिलाते हुए भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन निर्मित करने का काम है। अकेली एसयूसीआई (सी) अन्य जनवादी आन्दोलनों के साथ-साथ भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलनों को गठित कर रही है। हम वामपंथी एवं जनवादी पार्टियों की पाँतों के ईमानदार आम सदस्यों और जनता के अन्य समझदार तबकों से आह्वान करते हैं कि इस आन्दोलन में शामिल हों और जमीनी स्तर पर जन केमेटियां विकसित करते हुए इसे एक संगठित रूप देने में पहल कदमी करें। हम एक बार फिर दोहरा दें, याद दिला दें कि केवल जनवादी जनआन्दोलन की ऐसी लहरों का सांस्कृतिक वातावरण तैयार करना ही संस्थानीकृत भ्रष्टाचार से बचने का एक कारगर उपाय हो सकता हैं। भ्रष्टाचार के खतरे के खिलाफ जेहाद की अगुआई करने का सिर्फ यही एक रास्ता है। ■■

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-12/1123/2009-2011
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 of Every Month

गद्दाफी परिवार पर नाटो के हमले की साम्राज्यवाद-विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी ने की तीव्र निन्दा

लिबिया पर साम्राज्यवादी हमले के प्रसंग में इन्टरनेशनल एन्टी-इम्पीरियलिस्ट एण्ड पीपल्स सोलिडरिटी को-ऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव माणिक मुखर्जी ने 1 मई, 2011 को निम्नलिखित बयान दिया :

संयुक्तराज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड और इटली के नेतृत्व में नाटो फौजों ने बर्बर और दूर नियंत्रित मिसाइल हमले में 30 अप्रैल को मुयम्बर गद्दाफी के कनिष्ट बेटे और तीन नातियों की हत्या कर दी है। 19 मार्च से साम्राज्यवादी ताकतों की मुजरिमाना सर्वोच्य दर्जे की फौजी कार्रवाई, नो फ्लाई जोन का एलान, आकाश से दनादन बम-गोलीबारी आदि के नतीजतन यह घटना घटी है। उनके ये सब कार्यकलाप साबित करते हैं कि साम्राज्यवादियों के निर्देश पर तैयार हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का ही वे उल्लंघन कर रहे हैं। ये सब घटनाएं महाशक्तियों की अन्तर्राष्ट्रीय दस्युवृत्ति और अत्यन्त नकारात्मक कार्य के सिवाय और कुछ नहीं हैं, जो लिबिया की सम्प्रभुता और उस देश की जनता की स्वाधीनता को पैरों तले रौंद रही हैं। लिबिया के आम लोगों की रक्षा करने के 'मानवीय' बहाने से साम्राज्यवादियों का चरित्र पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और इराक के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्वाधीन साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा अफ्रिका के एक देश पर कब्जा करने का यह पहला कदम है। यह दिन के उजाले की तरह साफ है कि 'मानवीय' कार्यकलाप की बोली महज लोगों को ठगने के लिए है, उस देश की मूल्यवान सम्पदा की बेरोक-टोक लूट-खसोट करने के लिए है, उनका असली मकसद है मुयम्बर गद्दाफी को गद्दी से हटाकर लिबिया में 'शासक बदलना'। इन्टरनेशनल एण्टी इम्पीरियलिस्ट एण्ड पीपल्स सोलिडरिटी को-ऑर्डिनेशन कमेटी लिबिया में साम्राज्यवादी ताकतों के इस भयंकर हमले की तीव्र निन्दा करती है। गद्दाफी वहाँ सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे यह तय करने का पूरा अधिकार एकमात्र लिबिया की जनता का है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी-दूसरी साम्राज्यवादी ताकतों का इस मामले में निर्देश देने का या टांग अड़ाने का कोई अख्तियार नहीं है। लिबिया से अमेरिका नेतृत्वाधीन नाटो की फौज की हर तरह की फौजी दखलअंदाजी तुरन्त बंद करने और लिबिया की जनता को शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में फैसला लेने देने के लिए हम माँग करते हैं।

दिल्ली में जल बोर्ड के निजीकरण का विरोध

दिल्ली में जल बोर्ड के निजीकरण के सरकार के कदम के खिलाफ एसयूसीआई(सी) की बुराड़ी, मुकन्दपुर व भलस्वा स्थानीय कमेटियों द्वारा 22 मई को साइकिल मार्च करके रोष प्रदर्शन किया गया। साइकिल मार्च बुराड़ी चौक से शुरू हुआ और जहाँगीर पुरी में जाकर समाप्त हुआ। इसमें 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साइकिल मार्च के दौरान लगभग 10 जगह जनसभाएं, हस्ताक्षर अभियान और संघर्ष कोष संग्रह किया गया। पार्टी की राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्यों कॉमरेड हरीश त्यागी, कॉ. मनैजर चौरसिया ने जनसभाओं को सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार आम आदमी की प्रमुख मूलभूत जरूरत की चीज पानी को उनसे छीन कर भारी मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपति वर्ग के हवाले करने जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि सरकार की ऐसी जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ संगठित हों और जोरदार आन्दोलन खड़ा करें। उन्होंने 6 जुलाई को 5 लाख हस्ताक्षरों सहित लाल किला से मुख्यमंत्री कार्यालय तक होने वाले विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की भी लोगों से अपील की।

झारखण्ड में आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं का सम्मेलन

15 मई 2011 को जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में झारखण्ड आंगनवाड़ी कर्मचारी एसोशिएशन (जे.ए.के.ए.) द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पूर्वी सिंह भूम जिले के विभिन्न हिस्सों से आई 300 से ज्यादा आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं ने शिरकत की। आल इंडिया यूटीयूसी सचिव मण्डल के सदस्य तथा जेपीए के अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड अचिन्त्य सिन्हा सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन की अध्यक्षता आल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन झारखण्ड राज्य की अध्यक्षा कॉमरेड सरला माहतो ने की।

सम्मेलन में सोशल वेलफेयर, वुमन एण्ड चाइल्ड डेवलॉपमेंट डिपार्टमेंट झारखण्ड द्वारा जारी उस सर्कुलर का तीव्र प्रतिवाद किया गया जिसमें कहा गया है कि ''अब से आगे किसी भी पंचायत का मुखिया या वार्ड मेम्बर आंगनवाड़ी सेविका या सहायक को उसके पद से हटा सकता है।''

सम्मेलन में मांग की गई कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सेविका को उसकी सीनियरटी के मुताबिक पदोन्ति दी जाए।

कॉमरेड अचिन्त्य सिन्हा ने सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं से अपील की कि वे जेपीए और एईएफआई के नेतृत्व में जोरदार आन्दोलन गठित करने के लिए आगे आएं और एकमात्र क्रांतिकारी ट्रेड युनियन एआईयूटीयूसी मजबूत करें। सम्मेलन में पुष्पा माहतो, चांदमणी मुरमु, सोनामणी बास्के, सोमा डे, आरोती पॉल ने भी अपने विचार रखे। एक अस्थाई वर्किंग कमेटी के गठन का ऐलान किया गया। अंत में ऐलान किया गया कि हस्ताक्षर अभियान, सदस्यता अभियान आने वाले दिनों में चलाया जाएगा।

आगामी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सिलसिले में कॉमरेड माणिक मुखर्जी का नेपाल दौरा

इन्टरनेशनल एन्टी इम्पीरियलिस्ट एण्ड पीपल्स सोलिडरिटी कॉर्डिनेशन कमेटी के महासचिव और एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड माणिक मुखर्जी ने नेपाल की युनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) यूसीपीएन (एम) की केन्द्रीय कमेटी के चेयरमैन कॉमरेड प्रचण्ड से मुलाकात करने के लिए नेपाल का हाल ही में दौरा किया ताकि 7 से 9 नवम्बर, 2011 तक नेपाल में होने जा रहे आगामी अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन की तैयारियों को अन्तिम रूप दिया जा सके। उनकी मुलाकात 6 मई को काठमाण्डू स्थित यूसीपीएन (एम) के कार्यालय में हुई। यूसीपीएन (एम) पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेडस नीनू चापागेन और वसन्त भी चर्चा में मौजूद थे। इस वार्ता में यह निर्णय हुआ कि इस आगामी सम्मेलन का खुला अधिवेशन 7 नवम्बर को काठमाण्डू में सार्वजनिक स्थल पर होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य सम्मेलन से 3-4 दिन पहले, काठमाण्डू में एक संयुक्त प्रैस कान्फ्रेन्स की जायेगी जिसमें कॉमरेड माणिक मुखर्जी, कॉमरेड प्रचण्ड और अगर हो सका तो कॉमरेड राम्से क्लार्क भी शामिल होंगे।

सम्मेलन में लातिन अमेरिका, मध्य पूर्व, अफगानिस्तान, क्यूबा और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया पर साम्राज्यवादी हमले और आक्रमण के विशेष सन्दर्भ सहित अर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में साम्राज्यवादी हमलों के साथ-साथ सैनिक आक्रमण और किसी देश पर कब्जे पर आधारित थीम पर चर्चा होगी।

पाकिस्तान में गुप्त अमेरिकी सैन्य कार्रवाई एक जघन्य आतंकवादी कार्य

ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान की धरती पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की तीव्र निन्दा करते हुए हर तरह के आतंकवाद, अराजकता व गुण्डागर्दी के खात्मे के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ विश्वव्यापी जोरदार शान्ति आन्दोलन गठित करने का आह्वान करते हुए एसयूसीआई (सी) के महासचिव कामरेड प्रभाष घोष ने 9 मई, 2011 को निम्न बयान जारी किया :

अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकों द्वारा पाकिस्तान की सरकार और प्रशासन को कथित तौर पर अंधेरे में रखकर पाकिस्तान की धरती पर 1 मई, 2011 को आतंकवादी संगठन अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए गुप चुप की गई फौजी कार्रवाई की हम कड़ी निन्दा करते हैं। हमारा दृढ़ मत है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की यह कारस्तानी पाकिस्तान की सम्प्रभुता का बेशर्मी से हनन है और आतंकवाद की रोकथाम का वही बहाना बनाया जिसे बनाकर सभी अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, कूटनीतिक रीति-नीतियों व कानून-कायदों की धज्जिया उड़ाते हुए उन्होंने पहले भी, स्वतंत्र अफगानिस्तान व इराक के सीमा क्षेत्रों को रौंद डाला था और उन पर कब्जा कर लिया था। एक संदिग्ध बहाने से एक स्वतंत्र देश की सम्प्रभुता का हनन करने वाली ऐसी पूरी तरह एक चोरी-छिपे की गई फौजी कार्रवाई खुद एक आतंकवादी कार्य है। यह अन्तर्राष्ट्रीय गुण्डागर्दी की एक मुँह बोलती मिसाल है जो गुण्डागर्दी अमेरिकी साम्राज्यवादी द्वारा की जा रही है और दादागिरी और आधिपत्यवाद के बेशर्मी से अनुसरण के जरिए विश्व पर आधिपत्य जमाने की यह साम्राज्यवादी साजिश हमारा दृढ़ मत है कि विश्व शांति, स्वतंत्रता और राष्ट्रों की सम्प्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही है और दुनिया भर में अराजकता और आतंकवाद के पनपने और फैलने का मूल कारण है।

जहाँ अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने अनेक निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार होने का ओसामा बिन लादेन पर आरोप लगाया था, हकीकत यह है कि उन्होंने खुद उसे दबोचने के नाम पर उससे कहीं ज्यादा निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा और वस्तुतः अफगानिस्तान और इराक की ईंट से ईंट बजा दी।

केवल यही दर्शाता है कि अमेरिका साम्राज्यवादी दुनिया में सबसे खतरनाक आतंकवादी ताकत है। यह याद दिलाना प्रसंगानुकूल है कि ओसामा बिन लादेन असल में अमेरीकी साम्राज्यवादियों की ही सृष्टि है जिसकी मदद लेकर और अफगानिस्तान से सोवियत समथित फौजों को निकाल बाहर करने के बहाने अमेरीकी साम्राज्यवादियों ने वहाँ अपना नियंत्रण और आधिपत्य कायम करने की कोशिश की। न केवल अफगानिस्तान बल्कि समूची अरब दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता के विकास की प्रक्रिया को बाधित करने के ख़्याल से विद्वेष पूर्ण धार्मिक कट्टरता को उकसाने के उनके प्रयास में, अनेक बार उसने भरपूर समर्थन और सहयोग दिया था। उन्हीं अमेरीकी साम्राज्यवादियों ने जब यह देखा कि वह अब किसी काम का नहीं रहा तो उसका सफाया करने में जरा भी वक्त नहीं गवाँया। घोर फासीवादी ताकतों का यह बड़ा पुराना रण कौशल है जिस पर इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं।

तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि छिपता फिर रहा कोई व्यक्ति खतरनांक है पर उस निहत्थे व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसपर मुकदमा चलाने की बजाय मार देना, न केवल साफ दिखाई देने वाला कत्ल है बल्कि समूचे प्रकरण के सभी साक्ष्यों सबूतों को सदा के लिए खुदर्बुद कर देने की एक घिनौनी साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार इन्साफ करने के नाम पर ओबामा प्रशासन ने इन्साफ के आधार को ही पैरों तले रौंद डाला है। कथित रूप से एक विदेशी भूमि पर किसी गुप्त ठिकाने पर ओसामा को गोली मार देने की कार्रवाई ही एकदम मुजरिमाना कार्रवाई है और अगर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से यह जुर्म मुँह बंद कर मान लिया गया हम जोर देकर यह कहना और, तो चेतावनी देना चाहेंगे कि अमेरिकी साम्राज्यवादियों को किसी भी झूठे और बेबुनियादी बहाने से किसी भी देश में फौजी दखलअन्दाजी करने या धोखे से जो भी वे चाहें वह करने का लाइसेन्स मिल जाएगा।

यह सभी देशों के लोगों की संगठित प्रतिवादी आवाज ही होती है जो हर तरह की अराजक, आतंकवादी और गुण्डागर्दी की हरकतों के खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ तैयार करती है। इसलिए हमें दुनिया भर के सभी साम्राज्यवाद-विरोधी, जनवाद-पसन्द और शांतिकामी लोगों से आह्वान करते हैं कि वे अमेरिकी साम्राज्यवादियों कि इस घिनौनी कार्रवाई की निन्दा करें और उनकी दादागिरी व प्रभुत्ववाद के खिलाफ जोरदार आन्दोलन गठित करें जो अगर बेरोकटोक जारी रहने दिया गया तो हमें पूरा पूरा अंदेशा है कि आने वाले दिनों में यह और भी विकराल रूप धारण कर लेगा।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग. नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाषः 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com